सांध्य दैनिक

नई दृष्टिबिंदु

सच की शक्ति, जनता की दृष्टि

PRGI Reg No - CTHIN/25/A3746

वर्ष-01 अंक-136 | संपादक आलोक तिवारी | दुर्ग, शुक्रवार 05 जून 2026 | पृष्ठ 08 | मूल्य -2 रुपए

सु-विचार

"साफ-साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, परंतु वह धोखेबाज नहीं होता...!!"

अज्ञात...

धर्मशाला में वैभव सूर्यवंशी का धमाल : वनडे में जड़ा पहला तिहरा शतक, नाबाद 304 रन

रोहित शर्मा का 264 रन का रिकॉर्ड टूटा, अफगानिस्तान के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में युवा बल्लेबाज ने रचा इतिहास

नई दृष्टिबिंदु / धर्मशाला

हिमाचल के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में मंगलवार को क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार देखने को मिला। भारत और अफगानिस्तान के बीच आगामी वनडे सीरीज से पहले खेले गए प्रैक्टिस मैच में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने वनडे क्रिकेट का पहला तिहरा शतक जड़ दिया। उन्होंने नाबाद 304 रन की पारी खेलकर नया इतिहास रच दिया।

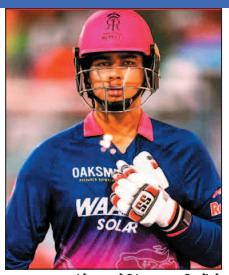

रोहित का 12 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त

वैभव ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के 2014 में श्रीलंका के खिलाफ बनाए 264 रन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 40वें ओवर में बिलाल शमी की गेंद पर चौका लगाकर जैसे ही वैभव

265 रन पर पहुंचे, पूरा ड्रेसिंग रूम तालियों से गूंज उठा। खुद रोहित शर्मा ने खड़े होकर मुस्कुराते हुए वैभव की पीठ थपथपाई।

17 गेंद में फिफ्टी, 31 गेंद में सेंचुरी

रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने उतरे वैभव ने शुरू से ही अफगानी गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। मोहम्मद नबी और राशिद खान जैसे गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। वैभव ने मात्र 17 गेंदों में अर्धशतक और 31 गेंदों में शतक पूरा कर सबको हैरान कर दिया।

सूर्यवंशी का आखिरी ओवर में पूरा हुआ तिहरा शतक

50वें ओवर में वैभव 287 रन पर खेल रहे थे। बिलाल शमी की पहली गेंद पर चौका, दूसरी पर दो रन और तीसरी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर छक्का लगाकर 299 रन पर पहुंचे। चौथी गेंद पर एक रन लेकर उन्होंने वनडे इतिहास की पहली ट्रिपल सेंचुरी पूरी की। वैभव 304 रन बनाकर नाबाद लौटे।

इस पारी की बदौलत भारत ने अफगानिस्तान के सामने 480 रन का विशाल लक्ष्य रखा। हालांकि मैच के नतीजे से ज्यादा चर्चा 19 साल के वैभव सूर्यवंशी की ऐतिहासिक पारी की हो रही है, जिसने पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों को चौंका दिया है।

स्कोरकार्ड पर एक नजर

भारत : 479/5 (50 ओवर)

वैभव सूर्यवंशी :	304 रन नाबाद
विराट कोहली :	78 रन
रोहित शर्मा :	54 रन
श्रेयस अय्यर :	47 रन
शुभमन गिल :	35 रन

विधायक देवेंद्र यादव ने उठाई मांग : मुख्यमंत्री उत्कर्ष योजना की प्रवेश प्रक्रिया फिर शुरू हो

ध्यानाकर्षण

मंत्री रामविचार नेताम को लिखा पत्र, बोले : प्रवेश रुकने से मेधावी छात्रों में निराशा

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना की वर्ष 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया फिर से शुरू करने की मांग की है। उन्होंने आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम को पत्र भेजकर जल्द कार्रवाई का अनुरोध किया है।

'ग्रामीण मेधावी छात्रों के लिए अहम योजना'

विधायक यादव ने कहा कि यह योजना अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के मेधावी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का अहम माध्यम है। पहले यह योजना जवाहर उत्कर्ष योजना के नाम से संचालित थी। इसके तहत छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और सर्वांगीण विकास का मौका मिलता है।

प्रवेश स्थगित होने से अभिभावकों में निराशा

उन्होंने बताया कि हाल ही में योजना की प्रवेश प्रक्रिया स्थगित करने के आदेश से अभिभावकों और विद्यार्थियों में निराशा है। प्रवेश रुकने से उन मेधावी छात्रों के भविष्य पर बुरा असर पड़ सकता है जो इस साल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे थे।

नई तिथि घोषित करने की मांग

विधायक देवेंद्र यादव ने मंत्री से मांग की है कि विद्यार्थियों के हित में प्रवेश प्रक्रिया और प्रवेश परीक्षा की नई तिथि घोषित की जाए। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना को जल्द फिर शुरू किया जाए ताकि पात्र विद्यार्थियों को लाभ मिल सके।

सलाखों के पीछे से सफलता की उड़ान

आजीवन कारावास भुगत रहे बंदी ने 12वीं प्रथम श्रेणी में की पास

अंग्रेजी में डिस्टिंक्शन, अब शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ाने का संकल्प

केंद्रीय जेल दुर्ग में 103 बंदियों ने पास की पहली से एमए तक की परीक्षा

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

केंद्रीय जेल दुर्ग में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक बंदी ने शिक्षा की ताकत से नई मिसाल कायम की है। सुपेला, भिलाई निवासी इस बंदी ने जेल में रहकर 12वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। अंग्रेजी विषय में डिस्टिंक्शन हासिल कर उसने यह साबित कर दिया कि हालात कैसे भी हों, लगन हो तो सफलता मिलती है।

2018 से काट रहा था सजा : यह बंदी वर्ष 2018 से भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा था। जेल आने से पहले वह अशिक्षित था। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के मार्गदर्शन और जेल प्रशासन की पाठशाला में उसने पढ़ाई शुरू की। सीमित संसाधनों के बीच कक्षा पहली से 12वीं तक का सफर तय किया।

शिक्षक बनने का संकल्प : सजा पूरी कर जेल से बाहर आने के बाद बंदी ने समाज की मुख्यधारा में सम्मान से जीने की इच्छा जताई है। उसने शिक्षक बनकर बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया है। यह उपलब्धि आत्मपरिवर्तन और पुनर्वास की दिशा में बड़ा कदम है।

जेल में 103 बंदी हुए पास : केंद्रीय जेल दुर्ग में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में महिला और पुरुष बंदियों ने कक्षा पहली से एमए अंतिम वर्ष तक की परीक्षा दी। कुल 103 बंदियों ने सफलता हासिल की। यह जेल परिसर में शिक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है।

जेल प्रशासन की अहम भूमिका : इस सफलता में केंद्रीय जेल दुर्ग के जेल अधीक्षक, जेल प्रशासन और पाठशाला के शिक्षकों की अहम भूमिका रही। उनके प्रयासों से बंदियों को न सिर्फ शिक्षा का मौका मिला, बल्कि बेहतर भविष्य की उम्मीद भी जगी।

यह कहानी बताती है कि अपराध व्यक्ति की पहचान नहीं होता। शिक्षा, संस्कार और सकारात्मक अवसर किसी भी जीवन को नई पहचान दे सकते हैं। केंद्रीय जेल दुर्ग में शिक्षा के जरिए हो रहा यह बदलाव सुधारात्मक न्याय व्यवस्था की सार्थकता का जीवंत उदाहरण है।

जेवरा-सिरसा स्थित आरडीके इंडस्ट्री का गोदाम सील, ऑस्ट्रेलियन कोक के अवैध भंडारण का आरोप

बीएसपी लोहा चोरी मामले में हुआ नया खुलासा

माइनिंग विभाग ने पुलिस की मौजूदगी में की कार्रवाई

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

बीएसपी में 250 टन लोहा चोरी के मामले की जांच के बीच एक नया मामला सामने आया है। जेवरा-सिरसा स्थित आरडीके इंडस्ट्री के गोदाम पर माइनिंग विभाग ने कार्रवाई करते हुए भंडारण क्षेत्र को सील कर दिया है। आरोप है कि यहां ब्लू डस्ट की आड़ में ऑस्ट्रेलियन कोक का अवैध भंडारण किया जा रहा था।

चूना डालकर की गई मार्किंग

जेवरा-सिरसा पुलिस को धमधा रोड स्थित आरडीके इंडस्ट्री में अवैध रूप से कोयला रखे जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद चौकी प्रभारी शामित मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस और माइनिंग विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। टीम ने कोयले का सैंपल लिया और संदिग्ध ब्लू डस्ट व ऑस्ट्रेलियन कोक के भंडारण स्थल को चूने से मार्किंग कर सील कर दिया।

माइनिंग विभाग ने स्पष्ट किया है कि सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना इस भंडारण क्षेत्र में किसी प्रकार का छेड़छाड़, अनाधिकृत प्रवेश या उत्पाद का उठाव नहीं किया जा सकता। अब सैंपल की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। अनियमितता की पुष्टि होने पर संबंधित कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

खुर्सीपार में 12 टन से ज्यादा कोक कोयला जब्त

क्राइम ब्रांच डीएसपी यदुमणि सिदार ने बताया कि गुरुवार को सूचना मिली कि खुर्सीपार गेट के पास एक गोदाम में बड़ी मात्रा में कोक कोयला रखा है। छापेमारी में ट्रक क्रमांक सीजी-07, बीसी-0977 से बीएसपी से चोरी किया गया करीब 12 टन से ज्यादा कोक कोयला जब्त किया गया। मामले में कार्रवाई कर खुर्सीपार पुलिस को सौंप दिया गया है।

पीएमओ तक पहुंचा मामला

बीएसपी लोहा चोरी का मामला हाईप्रोफाइल हो चुका है। इसमें कई बड़े उद्योगपतियों और राजनीतिक व्यक्तियों की संलिप्तता की चर्चा है। मामले की शिकायत पीएमओ तक पहुंच चुकी है। वहीं बीएसपी प्रबंधन ने अब तक चुप्पी साध रखी है और किसी भी अफसर की जवाबदेही तय नहीं की गई है। पुलिस का मानना है कि फरार संजय सिंह के पकड़े जाने के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं।

फरार संजय सिंह पर इनाम की तैयारी

लोहा चोरी मामले में फरार चल रहे ट्रांसपोर्टर संजय सिंह की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस अब उस पर इनाम घोषित करने की तैयारी कर रही है। पुलिस ने 10 बैंक खातों की पासबुक और 18 कंपनियों की चेकबुक भी जब्त की है। बैंक खातों की जांच में इस सिंडिकेट से जुड़े नए लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। एके ट्रेडर्स के गोदाम का संचालन करने वाला मो. सलीम भी अभी फरार है।

भाजपा ने नागेंद्र नाथ त्रिपाठी को बनाया राष्ट्रीय संगठक, दिल्ली में संभालेंगे जिम्मेदारी

जवाबदारी

यूपी, बिहार और झारखंड में संगठन को धार दे चुके हैं त्रिपाठी, आरएसएस पृष्ठभूमि से आते हैं

विशेष संवाददाता संदीप सिंह / नईदिल्ली

भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ संगठनकर्ता नागेंद्र नाथ त्रिपाठी को राष्ट्रीय संगठक की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उनका मुख्यालय दिल्ली रहेगा। इससे पहले वह बिहार और झारखंड के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री का दायित्व संभाल रहे थे।

यूपी में आठ साल रहे संगठन महामंत्री

आरएसएस पृष्ठभूमि से आने वाले नागेंद्र नाथ त्रिपाठी भाजपा के उन प्रमुख चेहरों में गिने जाते हैं जिन्होंने लंबे समय तक पर्दे के पीछे रहकर संगठन को मजबूत किया। वह करीब आठ साल तक उत्तर प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री रहे। 2003 में उन्हें यूपी का संगठन महामंत्री बनाया गया था। इस दौरान उन्होंने बूथ स्तर तक संगठन विस्तार, कार्यकर्ता प्रशिक्षण और चुनावी प्रबंधन पर खास जोर दिया।

साल 2011 में मिली थी बिहार की कमान

वर्ष 2011 में पार्टी ने उन्हें बिहार भाजपा का संगठन महामंत्री नियुक्त किया। इसके बाद अगस्त 2021 में भाजपा नेतृत्व ने उन्हें बिहार और झारखंड का क्षेत्रीय संगठन महामंत्री बनाया। यह पद पार्टी और संघ के बीच समन्वय के साथ चुनावी रणनीति और संगठन विस्तार के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है।

संघ और एबीवीपी में निभाई सक्रिय भूमिका

उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के बेलौली गांव में किसान परिवार में जन्मे नागेंद्र नाथ त्रिपाठी गिरिजा पति त्रिपाठी और गणेशा देवी के सबसे बड़े पुत्र हैं। स्कूली शिक्षा के दौरान बस्ती में उनका संपर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ। संघ में लंबे समय तक प्रचारक के रूप में काम किया और युवाओं के बीच वैचारिक गतिविधियों को मजबूत किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी उन्होंने जिम्मेदारी निभाई और कुशल संगठनकर्ता के रूप में पहचान बनाई।

भले ही सार्वजनिक मंचों पर उनकी मौजूदगी कम दिखती हो, लेकिन संगठनात्मक फैसलों और रणनीतिक बैठकों में उनकी भूमिका काफी प्रभावशाली मानी जाती है।

उपचुनाव में कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन : 543 पंचायत प्रतिनिधि जीते

2 नगर पंचायतों पर कब्जा, कांग्रेस बोली : शहरों-गांवों की जनता ने भाजपा को नकारा, कुशासन से नाराज लोग

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

नगर निगमों, नगर पंचायतों और पंचायतों के उपचुनाव में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि शहरों और गांवों की जनता ने भाजपा को नकार दिया है। पंचायतों के उपचुनाव में कांग्रेस के 543 से अधिक समर्थित प्रतिनिधि चुनाव जीते हैं।

निगमों व नगर पंचायतों में कांग्रेस की जीत

शुक्ला ने बताया कि जगदलपुर, बिलासपुर, कांकेर नगर निगम के वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशी जीते हैं। अंतागढ़ के वार्ड में भी कांग्रेस को जीत मिली है। नगर पंचायत घुमका और पलारी में कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। इसके अलावा नगर पंचायतों के 30 वार्डों में भी कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी रहे।

शिवनंदनपुर में 8 पार्षद कांग्रेस के

सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि शिवनंदनपुर नगर पंचायत में अध्यक्ष का पद भले भाजपा ने जीता, लेकिन 8 पार्षद कांग्रेस के जीतकर आए हैं। कांग्रेस वहां भी मजबूती से चुनाव जीतकर आई है।

'भाजपा का अवसान शुरू'

उन्होंने कहा कि तमाम सरकारी मशीनरी लगाने, सत्ता बल और धन बल का उपयोग करने तथा विपक्षी प्रत्याशियों को डराने धमकाने के बाद भी यह परिणाम आए हैं। यह बताते हैं कि राज्य में अब भाजपा का अवसान शुरू हो गया है। जनता ने भाजपा के कुशासन को नकार दिया है।

'2028 से पहले बदलाव का मूड'

शुक्ला ने कहा कि पंचायतों, निगमों और नगर पंचायतों के चुनाव परिणामों से साफ है कि छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा सरकार के ढाई वर्षों के कामों से नाराज है। वर्तमान परिणामों से जनता का परिवर्तन का मूड साफ दिख रहा है। 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार के खिलाफ जनता की नाराजगी सामने आने लगी है।

'एक पेड़, एक संकल्प : प्रकृति का संरक्षण ही मानवता का संरक्षण है' : अरुण वोरा

विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण कर दिया संदेश, पत्नी मंजू वोरा और बहन अर्चना भी रहीं साथ

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरुण वोरा ने धर्मपत्नी श्रीमती मंजू वोरा एवं बहन अचर्ना के साथ वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्वच्छ, सुरक्षित और हरित पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला है।

'प्रकृति संरक्षण हर नागरिक का दायित्व'

अरुण वोरा ने कहा कि वतर्मान समय में बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से पर्यावरण गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। प्रकृति का संरक्षण केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण, जल संरक्षण, प्लास्टिक के उपयोग में कमी और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण जैसे छोटे प्रयास भी पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

'पर्यावरण संरक्षण बने जनआंदोलन'

उन्होंने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का स्मरण कराता है। यदि पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप दिया जाए तो स्वच्छ, स्वस्थ और हरित भारत के निर्माण का सपना साकार हो सकता है। अरुण वोरा ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे 'एक पेड़, एक संकल्प' के साथ अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्रिय भागीदारी निभाते हुए प्रकृति को सुरक्षित रखने का संकल्प लें।

खेत बचाओ अभियान : कृषि मंत्री रामविचार नेताम व सांसद विजय बघेल हुए शामिल, किया पौधरोपण

दुर्ग। विश्व पर्यावरण दिवस पर महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, दुर्ग द्वारा सांकरा पाटन स्थित उद्यानिकी महाविद्यालय में 'खेत बचाओ अभियान' और 'एक पेड़ मां के नाम' कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि कृषि मंत्री रामविचार नेताम और विशिष्ट अतिथि सांसद विजय बघेल ने वृक्षारोपण किया। कृषि मंत्री ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग से मिट्टी की उर्वरता घट रही है। किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती अपनानी चाहिए। सांसद बघेल ने हर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाने की अपील की। कुलपति प्रो. रवि आर सक्सेना ने बताया कि इस वर्ष 800 पौधों के रोपण का लक्ष्य है। कार्यक्रम में कृषि प्रदशर्नी लगाई गई और किसानों को कृषि किट बांटे गए। भाजपा प्रदेश मंत्री जितेन्द्र वर्मा, सभापति नीलम चंद्राकर सहित कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।

खास खबर

पेपर लीक ने छीने युवाओं के सपने : जवाबदेही तय करे सरकार, छात्रों का विश्वास लौटाए – राहुल शर्मा

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

नीट समेत कई परीक्षाओं में गड़बड़ियों से लाखों अभ्यथिर्यो का भविष्य प्रभावित, कांग्रेस ने उठाए सवाल

देशभर में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं के मामलों को लेकर दुर्ग शहर कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राहुल शर्मा ने केंद्र और संबंधित एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की घटनाएं केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि करोड़ों युवाओं की मेहनत, सपनों और भविष्य पर सीधा प्रहार हैं। जारी प्रेस विज्ञप्ति में राहुल शर्मा ने कहा कि आज देश का युवा कठिन परिश्रम और वर्षो की तैयारी के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होता है, लेकिन बार-बार सामने आ रही पेपर लीक की घटनाएं उसकी उम्मीदों को तोड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि नीट सहित विभिन्न भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में सामने आए विवादों ने लाखों छात्र-छात्राओं को मानसिक तनाव और असुरक्षा के माहौल में धकेल दिया है।

"सिर्फ जांच की घोषणा पर्याप्त नहीं" : राहुल शर्मा ने कहा कि प्रत्येक पेपर लीक प्रकरण के बाद जांच की घोषणा कर देना समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। आवश्यक है कि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर और उदाहरणात्मक कारर्वाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति परीक्षा प्रणाली के साथ खिलवाड़ करने का साहस न कर सके। उन्होंने कहा कि परीक्षा की गोपनीयता और निष्पक्षता किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में युवाओं के विश्वास की आधारशिला होती है। यदि यही व्यवस्था संदेह के घेरे में आ जाए तो युवाओं का मनोबल टूटना स्वाभाविक है। **युवाओं में बढ़ रही निराशा चिंताजनक :** कांग्रेस महामंत्री ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में छात्र वर्षो का समय, आर्थिक संसाधन और अथक परिश्रम लगाते हैं। ऐसे में जब पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आती हैं तो मेहनती और ईमानदार अभ्यथिर्यो के साथ अन्याय होता है। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों और राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में गड़बड़ियों के आरोपों ने युवाओं के बीच गहरी निराशा पैदा की है। यह स्थिति केवल शैक्षणिक संकट नहीं, बल्कि सामाजिक चिंता का विषय भी है। कई अवसरों पर परीक्षा विवादों और भविष्य को लेकर बढ़ी मानसिक परेशानियों के कारण छात्रों द्वारा आत्महत्या जैसे दुखद कदम उठाए जाने की खबरें भी सामने आई हैं, जो पूरे समाज के लिए गंभीर चेतावनी हैं।

"देश का युवा जवाब मांग रहा है" : राहुल शर्मा ने कहा कि देश का युवा अब जवाब मांग रहा है। उसकी मेहनत, समय और परिवारों की उम्मीदों का मूल्य है। सरकार को अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए ऐसी मजबूत और पारदर्शी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए, जिससे परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित, निष्पक्ष और विश्वसनीय बन सके। उन्होंने मांग की कि परीक्षा संचालन से जुड़े तंत्र को तकनीकी रूप से और अधिक सुदृढ़ किया जाए, पेपर लीक मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष व्यवस्था बनाई जाए तथा दोषियों को कड़ी सजा सुनिश्चित की जाए। **शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की आवश्यकता :** राहुल शर्मा ने कहा कि हाल के महीनों में कांग्रेस सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों और छात्र समूहों द्वारा भी परीक्षा प्रणाली में सुधार, जवाबदेही तय करने और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की जाती रही है। उन्होंने कहा कि यह किसी एक दल का नहीं, बल्कि देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़ा विषय है।

प्रेम प्रसंग के शक में बाउंसर की हत्या, आंखों में मिर्च झोंक पत्थर से किया हमला

कोटा, बिलासपुर। कोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अमने के पास एक युवक की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। पुरानी रंजिश और कथित प्रेम प्रसंग के विवाद में आरोपियों ने युवक की आंखों में मिर्च झोंककर पत्थर से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान ग्राम पथर्रा निवासी निखिल गोस्वामी, पिता गजेंद्र गोस्वामी, उम्र 28 वर्ष के रूप में हुई है। निखिल बिलासपुर के एक बार में बाउंसर का काम करता था और जिम संचालन से भी जुड़ा था। गुरुवार रात वह कोटा स्थित जिम आया था। इस दौरान वह ग्राम पथर्रा के दो युवकों के साथ शराब पीने अमने गांव जाने वाले रोड किनारे बैठा था।

रात करीब 9:30 बजे कुछ युवक दो मोटरसाइकिल से आए और निखिल की आंखों में मिर्च पाउडर झोंक दिया। इसके बाद आरोपियों ने भारी पत्थर से उस पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल निखिल को परिजन तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटा ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत देखते हुए उसे सिम्स बिलासपुर रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह, डीएसपी नूपुर उपाध्याय और कोटा थाना प्रभारी आकाश चौधरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस की प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग और चरित्र शंका से जुड़ा बताया जा रहा है।

तेलुगु समाज ने दिखाई आंध्र की संस्कृति की झलक–सांसद बघेल

मनिनम्मा सम्बरालु शीतला माता महोत्सव में शामिल हुए सांसद

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

वार्ड क्रमांक 45, जोन-2 अल्लपूरी सीता राम चौक बालाजी नगर खुर्शीपार में तेलुगु समाज द्वारा श्री श्री श्री मनिनम्मा सम्बरालु सीतला माता महोत्सव श्रद्धा और सांस्कृतिक उल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद विजय बघेल शामिल हुए। उन्होंने नगर भ्रमण के दौरान विभिन्न झांकियों का अवलोकन किया और सीतला माता की पूजा अचर्ना कर क्षेत्र की सुख समृद्धि और शांति की कामना की।

'भिलाई मिनी भारत है': विजय बघेल

सांसद विजय बघेल ने कहा कि भिलाई वास्तव में मिनी भारत है। यहां देश के अलग अलग राज्यों के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं के साथ मिल जुलकर रहते हैं। तेलुगु समाज का यह महोत्सव आंध्र प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत उदाहरण है। यहां की झांकियां और प्रस्तुतियां देखकर ऐसा लगता है मानो हम आंध्र प्रदेश की धरती पर पहुंच गए हों।

विशाखापट्टनम के कलाकारों ने बांधा समां

संस्कृति समिति के अध्यक्ष के. श्याम सुंदर राव ने बताया कि यह महोत्सव वर्षो से तेलुगु समाज की आस्था का प्रतीक रहा है। इस वर्ष भी आंध्र की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को दर्शाती झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। नगर भ्रमण यात्रा में भगवान बालाजी की झांकी, कोबरा डांस, अलारु नृत्य, नौ दुर्गा स्वरूप, वडुका पडम, अक्का अलाडु, जालरी संस्कृति तथा विशाखापट्टनम की झलकियों ने लोगों का मन मोह लिया। विशाखापट्टनम से आए कलाकारों के कोबरा डांस और पारंपरिक नृत्यों ने दशर्कों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यात्रा के दौरान "गोविंदा-गोविंदा" के जयघोष से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। महोत्सव में तेलुगु युवता समिति के वरिष्ठजन, पदाधिकारी, युवा और महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। श्रद्धालुओं ने धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेकर माता सीतला का आशीर्वाद लिया। आयोजन ने सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक एकता और भारतीय परंपराओं के संरक्षण का संदेश दिया।

शीतला माता महोत्सव : तेलुगु युवता समिति के कार्यक्रम में शामिल हुए जनप्रतिनिधि

विशेष रूप से उपस्थित थे पार्षद श्याम सुंदर राव

तेलुगु युवता समिति, वार्ड 45 बालाजी नगर द्वारा जोन-2 खुर्सीपार में श्रीश्रीश्री मंकिनम्मा सम्बरालु शीतला माता महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और समाज के लोग शामिल हुए।

जनप्रतिनिधियों की रही उपस्थिति

महोत्सव में आयोजन समिति के अध्यक्ष एवं वार्ड 45 के पार्षद, पूर्व सभापति भिलाई नगर निगम श्री श्याम सुंदर राव विशेष रूप से उपस्थित रहे। उनके साथ भिलाई नगर निगम के उप नेताप्रतिपक्ष श्री दया सिंह भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

इस अवसर पर सर्व समाज कल्याण समिति के पदाधिकारी और सदस्य, समाज की वरिष्ठ माताएं, बहनें तथा युवा साथी भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सभी ने माता शीतला की पूजा अचर्ना कर क्षेत्र में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। मेले में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ पूजा संपन्न हुई। श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। आयोजन को सफल बनाने में तेलुगु युवता समिति के सदस्यों का विशेष योगदान रहा।

खुर्सीपार में शीतला माता महोत्सव में कन्हैया सोनी हुए शामिल, आयोजकों को दी बधाई

खुर्सीपार में तेलुगु समाज द्वारा शीतला माता महोत्सव मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कन्हैया सोनी प्रमुख रूप से शामिल हुए। कन्हैया सोनी ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि समिति के अध्यक्ष एवं नगर निगम भिलाई के पूर्व सभापति श्याम सुंदर राव और उनकी पूरी टीम को इस सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। महोत्सव में बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने माता शीतला की पूजा अचर्ना की। श्रद्धालुओं ने मेले का आनंद लिया और क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। आयोजन में तेलुगु समाज के वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और युवाओं की सक्रिय भागीदारी रही।

7.88 करोड़ रुपये के मादक पदार्थों का नष्टीकरण, दुर्ग रेंज की बड़ी कार्रवाई

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

दुर्ग रेंज की उच्च स्तरीय ड्रग्स डिस्पोजल समिति ने गुरुवार को थाना पुलगांव में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक प्रकरण में जप्त लगभग 7.88 करोड़ रुपये मूल्य के मादक पदार्थों का वैधानिक प्रक्रिया के तहत नष्टीकरण किया। यह कार्रवाई पुलिस मुख्यालय रायपुर एवं छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार की गई।

जानकारी के अनुसार थाना पुलगांव के अपराध क्रमांक 247/2026, धारा 8 एवं 18 एनडीपीएस एक्ट के तहत जप्त किए गए मादक पदार्थों को भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) के एसएमएस-3 प्लांट में निर्धारित मानकों के अनुरूप नष्ट किया गया। नष्टीकरण से पूर्व पर्यावरण विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों से आवश्यक अनुमति प्राप्त की गई थी। उच्च स्तरीय ड्रग्स डिस्पोजल समिति के अध्यक्ष एवं दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अभिषेक शांडिल्य के नेतृत्व में संपन्न इस कारर्वाई में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं उप पुलिस महानिरीक्षक विजय अग्रवाल तथा आबकारी उपायुक्त शशांक कुमार भी उपस्थित रहे।

पुलिस के अनुसार प्रकरण में आरोपियों से लगभग 14 लाख 30 हजार 100 नग अफीम के पौधे, जड़, तना, पत्ती, फूल एवं फल, कुल 62,422.2 किलोग्राम वजन के साथ ही 62.540 किलोग्राम अफीम डोडा एवं 572 ग्राम अफीम युक्त सूखा मिश्रित डोडा बुक्की जप्त की गई थी। जप्त सामग्री का अनुमानित बाजार मूल्य करीब 7.88 करोड़ रुपये आंका गया है।

न्यायालयीन एवं वैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद मादक पदार्थों का सुरक्षित और विधिसम्मत नष्टीकरण किया गया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) सुखनंदन राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर सत्य प्रकाश तिवारी, उप पुलिस अधीक्षक पनिक राम कुजूर, उप पुलिस अधीक्षक शिल्पा साहू सहित पर्यावरण विभाग और बीएसपी के अधिकारी मौजूद रहे।

दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन, परिवहन, बिक्री अथवा सेवन से संबंधित किसी भी गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। पुलिस ने कहा कि नशे के विरुद्ध अभियान को सफल बनाने में जनता का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है।

दुर्ग में तीन अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को होम आइसोलेशन में रखा

इबोला के लक्षण नहीं, कांगो, इथोपिया और युगांडा से आए यात्री पूरी तरह स्वस्थ, 21 दिन तक होगी निगरानी

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

दुर्ग जिले में अफ्रीकी देशों से आए तीन अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को 21 दिन के लिए होम आइसोलेशन में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इनमें इबोला वायरस के कोई लक्षण नहीं मिले हैं। तीनों यात्री असिम्प्टमैटिक हैं और पूरी तरह स्वस्थ हैं।

जिला प्रशासन के मुताबिक एक यात्री 31 मई को कांगो से दुर्ग पहुंची। दो यात्री 2 जून को भिलाई आए, जिनमें से एक इथोपिया और एक युगांडा से आया है। नो सिम्टोमैटिक और नो हिस्ट्री ऑफ कॉनटैक्ट होने के कारण तीनों को कैटेगरी-1 में रखकर होम आइसोलेशन किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम सुबह और शाम टेलीफोन से उनकी सेहत की जानकारी ले रही है।

दिक्कत होने पर तुरंत सूचना देने के निर्देश

यात्रियों को किसी भी तरह की तकलीफ होने पर ट्रेसिंग टीम, स्वास्थ्य विभाग, कंट्रोल रूम या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय को तुरंत सूचना देने को कहा गया है।

इबोला से निपटने के लिए जिला स्तरीय रैपिड रिस्पांस टीम बनाई गई है। इसमें जिला सर्विलेंस अधिकारी डॉ. सी.बी.एस. बंजारे, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. दिव्या श्रीवास्तव, जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. रश्मि ग्लैड और जिला महामारी अधिकारी रितिका सोनवानी शामिल हैं। टीम की जानकारी जिले की वेबसाइट https://durg.gov.in पर उपलब्ध है।

इबोला वायरस : लक्षण और जांच

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इबोला के लक्षणों में बुखार, उल्टी, पेट दर्द, जोड़ों में दर्द, अत्यधिक थकान, सिर दर्द और अधिक वाटरी डायरिया शामिल हैं। यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क और बॉडी फ्लूइड से फैलता है। जांच के लिए मुख्य रूप से आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाता है।

साउथ अफ्रीका में मिला था वायरस

साउथ अफ्रीका में इबोला वायरस 5 मई 2026 को मिला था। 15 मई को इसकी पहचान हुई और 17 मई को डब्ल्यूएचओ ने प्रमाणित किया। इसके बाद अफ्रीकी देशों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर क्लिनिकल स्क्रीनिंग की जा रही है। रिस्क के आधार पर उन्हें कैटेगरी-1 से 3 में रखा जा रहा है। दुर्ग आए तीनों यात्री कैटेगरी-1 में हैं।

भिलाई में 6 जून को 'एक शाम बशीर बद्र के नाम' ग़जल संध्या, प्रवेश नि :शुल्क

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के क्रीड़ा, सांस्कृतिक एवं नागरिक सुविधाएं विभाग द्वारा पद्मश्री डॉ. बशीर बद्र की स्मृति में विशेष ग़जल संध्या एक शाम बशीर बद्र के नाम का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम 6 जून 2026 को महात्मा गांधी कला मंदिर में सायं 7:30 बजे से होगा।

प्रसिद्ध कलाकार करेंगे शिरकत

कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध ग़जल गायिका डॉ. साधना रहाटगांवकर, युवा ग़जल गायक परन राज भाटिया तथा अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भजन एवं ग़जल गायक प्रभंजय चतुर्वेदी अपनी प्रस्तुतियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करेंगे। इस संध्या में पद्मश्री डॉ. बशीर बद्र की कालजयी रचनाओं और लोकप्रिय ग़जलों के माध्यम से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी जाएगी।

पद्मश्री डॉ. बशीर बद्र को समर्पित कार्यक्रम में साधना रहाटगांवकर और प्रभंजय चतुर्वेदी देंगे प्रस्तुति

खैरागढ़ और भिलाई के कलाकार देंगे संगत

संगत के लिए इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ के ख्यातिलब्ध कलाकारों के साथ भिलाई के राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। संगीत, साहित्य और ग़जल की समृद्ध परंपरा को समर्पित यह आयोजन सांस्कृतिक रसिकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा।

प्रवेश नि:शुल्क

भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन ने नगरवासियों, साहित्य एवं संगीत प्रेमियों से इस विशेष ग़जल संध्या में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने की अपील की है। कार्यक्रम में प्रवेश पूर्णतः नि:शुल्क रहेगा।

जनता तक पहुंचे योजनाओं का वास्तविक लाभ, प्रशासन जवाबदेही के साथ करे कार्य : मुख्यमंत्री साय

बैठक में विकास कार्यों, राजस्व प्रकरणों, पेयजल, स्वास्थ्य और खरीफ तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

शासन प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जनसमस्याओं का संवेदनशील, पारदर्शी और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के अंतर्गत बिलासपुर प्रवास के दौरान बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, सक्ती एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों के अधिकारियों की संयुक्त समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही। मुख्यमंत्री श्री साय ने विकास कार्यों की प्रगति, राजस्व मामलों, पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं तथा आगामी खरीफ सीजन की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की।

मुख्यमंत्री ने राजस्व मामलों की समीक्षा करते हुए समय-सीमा से बाहर तथा एक वर्ष से अधिक समय से लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और अन्य राजस्व प्रकरण सीधे नागरिकों के जीवन और आजीविका से जुड़े होते हैं। ऐसे मामलों में अनावश्यक विलंब आमजन की परेशानी बढ़ाता है, इसलिए इनके त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं पर रखें विशेष निगरानी : मुख्यमंत्री श्री साय ने ग्रीष्मकालीन परिस्थितियों को देखते हुए सभी जिलों में पेयजल व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में पेयजल संकट उत्पन्न न हो, इसके लिए निरंतर निगरानी और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को आगामी वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए संभावित मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार के लिए अग्रिम तैयारी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं और मूलभूत सुविधाओं के संबंध में किसी प्रकार की असुविधा न हो, यह प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी है।

बैठक में मुख्यमंत्री ने आगामी खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए खाद एवं बीज की उपलब्धता, भंडारण और वितरण व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद एवं बीज उपलब्ध कराया जाए तथा वितरण व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी और व्यवस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने पश्चिम एशिया की परिस्थितियों के कारण डीएपी उर्वरक की सीमित उपलब्धता का उल्लेख करते हुए किसानों को वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग के लिए जागरूक करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि एसएसपी, यूरिया, नैनो यूरिया तथा नैनो डीएपी जैसे विकल्पों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। वैज्ञानिक खेती और संतुलित उर्वरक उपयोग से उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ खेती की लागत भी कम की जा सकती है।

कृषि क्षेत्र में बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी : मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि महिलाओं को आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण और आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे तकनीक आधारित कृषि गतिविधियों से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकें। इससे कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का विस्तार होगा और महिलाओं के लिए रोजगार एवं आय के नए अवसर भी सृजित होंगे।

जनभागीदारी से सफल हो रहा सुशासन तिहार: मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वे स्वयं प्रदेश में आयोजित समाधान शिविरों में शामिल होकर आम नागरिकों से सीधे संवाद कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी के बावजूद शिविरों में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि जनता का शासन और प्रशासन के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है।

उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार केवल शिकायतों के निराकरण का अभियान नहीं, बल्कि सरकार और जनता के बीच विश्वास एवं संवाद को मजबूत करने का माध्यम है। मुख्यमंत्री ने महतारी वंदन योजना की 28वीं किश्त जारी होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, सतत निगरानी और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने का आह्वान करते हुए कहा कि शासन की प्रत्येक योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही सुशासन का वास्तविक उद्देश्य है। यही विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का आधार बनेगा।

बैठक में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े, विधायक अमर अग्रवाल, धरमलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह, सुशांत शुक्ला, दिलीप डहरिया, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, विशेष सचिव रजत बंसल, संभागायुक्त

खास खबर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भिखमपुरा के पंचमुखी सिद्ध हनुमान मंदिर में की पूजा-अर्चना

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुशासन तिहार के अंतर्गत सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के ग्राम भिखमपुरा पहुंचकर स्वामी शिवानंद विद्यापीठ एवं गौसेवा आश्रम परिसर स्थित श्री पंचमुखी दक्षिणाभिमुख सिद्ध हनुमान मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, खुशहाली, उत्तम स्वास्थ्य और राज्य की निरंतर प्रगति की कामना करते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की समृद्धि, जनकल्याण और सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की मंगलकामना की।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय इन दिनों सुशासन तिहार के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों के ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों का सतत दौरा कर रहे हैं। इस अभियान के माध्यम से वे सीधे आमजन से संवाद स्थापित कर शासन की योजनाओं और सेवाओं के जमीनी क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तथा समस्याओं के त्वरित निराकरण की दिशा में आवश्यक निर्देश भी दे रहे हैं।

भिखमपुरा प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने गौसेवा आश्रम परिसर में आयोजित चौपाल में ग्रामीणों से आत्मीय संवाद किया। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं, सुझाव और अपेक्षाएं सुनीं तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से उन्हें मिल रहे लाभों की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार शासन और जनता के बीच विश्वास को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसके जरिए प्रशासन सीधे लोगों तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कर रहा है। इस अवसर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, स्थानीय नागरिक, आश्रम से जुड़े सदस्य तथा जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित थे।

मेडिटेशन को जीवनशैली का हिस्सा बनाएं - राज्यपाल रमेन डेका

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने कहा है कि मेडिटेशन (ध्यान) को जीवनशैली का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। आज के तनावपूर्ण और व्यस्त जीवन में ध्यान मानसिक शांति, एकाग्रता और कार्यकुशलता बढ़ाने का प्रभावी माध्यम है। लोक भवन में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आयोजित तीन दिवसीय ध्यान शिविर के दूसरे दिन राज्यपाल श्री रमेन डेका भी उपस्थित रहे। इस दौरान हार्टफुलनेस संस्था, अमलेश्वर से आए प्रशिक्षकों ने अधिकारियों और कर्मचारियों को ध्यान की विभिन्न विधियों की जानकारी दी तथा उनका व्यावहारिक अभ्यास भी कराया।

राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान समय में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और कार्यभार के कारण तनाव एक सामान्य समस्या बन गया है। ऐसे में ध्यान व्यक्ति को मानसिक संतुलन बनाए रखने, तनाव कम करने और सकारात्मक ऊर्जा के साथ कार्य करने में सहायता करता है। राज्यपाल ने अधिकारियों और कर्मचारियों से प्रतिदिन कुछ समय ध्यान के लिए निकालने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि नियमित ध्यान का अभ्यास व्यक्ति के जीवन में आत्मिक संतोष, सकारात्मकता और अद्भुत आनंद का अनुभव कराता है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में बेहतर संतुलन स्थापित कर सकता है। शिविर में हार्टफुलनेस संस्था, अमलेश्वर के प्रशिक्षकों ने ध्यान के महत्व, उसकी प्रक्रिया और दैनिक जीवन में उसके लाभों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने प्रतिभागियों को ध्यान के व्यावहारिक सत्र में शामिल कराकर उसका अनुभव भी कराया। इस अवसर पर प्रशिक्षकों ने राज्यपाल श्री डेका को मेडिटेशन और आत्मिक विकास से संबंधित पुस्तकें भी भेंट कीं।

बिलासपुर बनेगा छत्तीसगढ़ का प्रमुख एजुकेशन हब : युवाओं के सपनों को मिलेगी एक नई उड़ान

120 करोड़ रुपये की परियोजना युवाओं को देगी अध्ययन, आवास और प्रतियोगी परीक्षा तैयारी की सुविधाएं

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर-बिलासपुर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत बिलासपुर प्रवास के दौरान मधुबन-जूना बिलासपुर क्षेत्र में निर्माणाधीन नालंदा परिसर एवं एजुकेशन हब का निरीक्षण कर परियोजना की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने निर्माण कार्यों का अवलोकन करते हुए अधिकारियों को गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह परियोजना प्रदेश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोलेगी और बिलासपुर को शिक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षा तैयारी के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करेगी।

इस अवसर पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विधायक अमर अग्रवाल, धरमलाल कौशिक, सुशांत शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, महापौर श्रीमती पूजा विधानी, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, विशेष सचिव रजत बंसल, संभागायुक्त सुनील जैन, पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग, कलेक्टर संजय अग्रवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह सहित जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि बिलासपुर में प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में विद्यार्थी सीजीपीएससी, यूपीएससी, नीट, जेईई, एसएससी, बैंकिंग, व्यापम तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आते हैं। इन विद्यार्थियों को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आधुनिक अध्ययन वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगभग 13 एकड़ शासकीय भूमि पर 120 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक एजुकेशन हब विकसित किया जा रहा है।

परियोजना के अंतर्गत नालंदा डिजिटल पब्लिक लाइब्रेरी, 300-300 सीटर बालक एवं बालिका छात्रावास, आधुनिक शैक्षणिक ब्लॉक तथा विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। एक ही परिसर में अध्ययन, आवास और शैक्षणिक संसाधनों की उपलब्धता विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उत्कृष्ट वातावरण प्रदान करेगी। इससे प्रदेश के विभिन्न जिलों से आने वाले विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलेगा।

अधिकारियों ने बताया कि परिसर में 48 बड़े रेंटल हॉल का निर्माण भी किया जा रहा है। इससे नगर निगम के लिए दीर्घकालिक और स्थायी आय का स्रोत विकसित होगा। पीपीपी मॉडल पर विकसित की जा रही इस परियोजना का संचालन वित्तीय दृष्टि से भी आत्मनिर्भर होगा तथा नगर निगम पर अतिरिक्त आर्थिक भार नहीं आएगा।

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सरकार युवाओं को बेहतर संसाधन, आधुनिक अधोसंरचना और प्रतिस्पर्धी वातावरण उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि नालंदा परिसर एवं एजुकेशन हब केवल एक भवन परियोजना नहीं, बल्कि युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं को नई दिशा देने वाला ज्ञान केंद्र है।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि परियोजना पूर्ण होने के बाद बिलासपुर की पहचान प्रदेश ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख शैक्षणिक एवं प्रतियोगी परीक्षा तैयारी केंद्र के रूप में स्थापित होगी। यह एजुकेशन हब हजारों विद्यार्थियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के साथ उनके उज्ज्वल भविष्य की मजबूत आधारशिला बनेगा।

मुख्यमंत्री ने जारी की महतारी वंदन योजना की 28वीं किस्त

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बिलासपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना की 28वीं किस्त जारी करते हुए प्रदेश की 68 लाख 54 हजार महिलाओं के बैंक खातों में 642 करोड़ 27 लाख 77 हजार 950 रुपये की राशि अंतरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं का सम्मान, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है तथा महतारी वंदन योजना इस दिशा में एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी पहल के रूप में सामने आई है।

श्री साय ने कहा कि किसी भी समाज और राज्य की प्रगति तब तक पूर्ण नहीं हो सकती, जब तक महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और सामाजिक रूप से सम्मानित न किया जाए। महतारी वंदन योजना महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ उनके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूत कर रही है। यह योजना प्रदेश की माताओं और बहनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का आधार बन रही है।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 1 मार्च 2024 से प्रारंभ हुई महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। योजना से प्राप्त राशि का उपयोग महिलाएं परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण तथा छोटे-छोटे स्वरोजगार कार्यों में कर रही हैं। इससे परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ महिलाओं की सामाजिक भागीदारी भी बढ़ी है। जून 2026 में जारी 28वीं किस्त के साथ ही योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश की महिलाओं को कुल 18 हजार 165 करोड़ 19 लाख रुपये से अधिक की सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है। यह राशि महिलाओं के जीवन में आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

जनचौपाल में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुनी जनता की बात, विकास कार्यों की दी सौगात

सपेरा समाज के लिए सामुदायिक भवन, मंगल भवन, सीसी रोड और तालाब सौंदर्यीकरण सहित कई विकास कार्यों की घोषणा

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुशासन तिहार के अंतर्गत आज सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के ग्राम भीखमपुरा में आयोजित जनचौपाल में ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा क्षेत्र के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। गौशाला परिसर में आयोजित जनचौपाल में मुख्यमंत्री पारंपरिक खाट पर बैठकर ग्रामीणों, महिलाओं, जनप्रतिनिधियों एवं स्व-सहायता समूहों की महिलाओं से रूबरू हुए और उनकी समस्याओं, सुझावों तथा अपेक्षाओं की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सुशासन तिहार केवल एक प्रशासनिक अभियान नहीं, बल्कि शासन और जनता के बीच विश्वास, संवाद और जवाबदेही को मजबूत करने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गांव-गांव पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रही है और उनके त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आमजन से प्राप्त आवेदनों और शिकायतों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की योजनाओं का वास्तविक मूल्यांकन तभी संभव है जब सरकार स्वयं लोगों के बीच जाकर उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करे। इसी उद्देश्य से प्रदेशभर में जनचौपालों और समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने जनचौपाल में उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और जनकल्याण का लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसानों के हित में संचालित विभिन्न योजनाओं, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना तथा महिला स्व-सहायता समूहों के सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि उनका लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक पहुंचे।

जनचौपाल के दौरान ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत मांगों पर मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने सपेरा समाज के लिए सर्वसुविधायुक्त सामुदायिक भवन के निर्माण, बस्ती क्षेत्र में मंगल भवन निर्माण, गांव की आंतरिक गलियों में सीसी रोड निर्माण तथा चंडी मंदिर के समीप स्थित डबरी तालाब के सौंदर्यीकरण की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने ग्राम की प्राथमिक शाला का नामकरण पंडित इंदायानंद पाणिग्राही के नाम पर किए जाने की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क तथा आजीविका के क्षेत्र में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने ग्रामीणों से शासन की योजनाओं का लाभ लेने और विकास कार्यों में सक्रिय सहभागिता निभाने का आग्रह किया।

इस अवसर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि भीषण गर्मी के बीच मुख्यमंत्री का सीधे गांव पहुंचकर लोगों से संवाद करना उनकी संवेदनशील कार्यशैली और जनसेवा के प्रति समर्पण का परिचायक है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में विकास और सुशासन को नई दिशा मिली है तथा शासन की योजनाओं का लाभ तेजी से अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव रजत बंसल सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे।

विश्व पर्यावरण पर राज्यपाल रमेन डेका ने दिया जल और पर्यावरण संरक्षण का संदेश

पानी है तो पेड़ हैं और पेड़ हैं तो पानी है -डेका

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका ने प्रदेशवासियों से पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बढ़ते पर्यावरणीय संकट और भविष्य में संभावित जल संकट को देखते हुए प्रत्येक नागरिक को प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। राज्यपाल ने कहा कि जल और जंगल एक-दूसरे के पूरक हैं। यदि पानी रहेगा तो पेड़-पौधे सुरक्षित रहेंगे और यदि पेड़ रहेंगे तो जल स्रोतों का संरक्षण संभव होगा।

राज्यपाल ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़कर अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। उन्होंने कहा कि एक पौधा लगाना केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य में योगदान है। वृक्ष पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने, वर्षा चक्र को मजबूत करने और भूजल स्तर को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

राज्यपाल ने कहा कि देश और दुनिया के अनेक क्षेत्रों में जल स्रोत लगातार घट रहे हैं। भविष्य में जल संकट और गंभीर हो सकता है। वर्षा जल संचयन, जल का विवेकपूर्ण उपयोग, तालाबों और जल स्रोतों का संरक्षण तथा वृक्षारोपण जैसे प्रयास सामूहिक रूप से किए जाएं तो आने वाले वर्षों में जल संकट की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सकता है।

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका लोक भवन तथा नया रायपुर स्थित निर्माणाधीन लोक भवन परिसर में वृक्षारोपण करेंगे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे जनभागीदारी के माध्यम से एक व्यापक सामाजिक अभियान का स्वरूप दिया जाना चाहिए। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों से संकल्प लेने का आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, जल बचाएं और प्रकृति के संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाएं।

कर्मचारियों को पौधे भेंट

विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर राज्यपाल श्री डेका ने लोक भवन के कर्मचारियों को पौधे भेंट किए तथा उन्हें अपने घरों एवं आसपास पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर लोक भवन के सभी कर्मचारियों के लिए निशुल्क पौधों के वितरण की व्यवस्था की गई है।

पर्यावरण संरक्षण के लिए जन जागरूकता बढ़ाएं

राज्यपाल रमेन डेका से लोकभवन में रायपुर वन वृत्त के संभागीय वन अधिकारी मयंक पाण्डेय ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान राज्यपाल ने 5 जून को आयोजित होने वाले विश्व पर्यावरण दिवस के लिए वन विभाग द्वारा की जा रही तैयारियों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। राज्यपाल ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने तथा अधिकाधिक जनसहभागिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक दिवस तक सीमित न रहकर सतत सामाजिक दायित्व के रूप में अपनाया जाना चाहिए।

संपादकीय

पद पर हैं और विनम्र नहीं है यही समस्या है

किसी भी देश समाज में दो तरह के लोग होते हैं। एक यथास्थितिवादी होते हैं यानी हर तरह के सुधार के विरोधी। जो यह मानकर चलते हैं कि जो व्यवस्था है, वही अच्छी है। उसमें सुधार की कोई जरूरत नहीं है। जब भी किसी क्षेत्र में कोई सुधार किया जाता है तो यथास्थितिवादी उसका विरोध करते हैं। वह मौके की ताक में रहते हैं कि किसी क्षेत्र में सुधार के बाद भी कोई गड़बड़ी तो हो, वह उस गड़बड़ी को विरोध करते हैं यह साबित करने लग जाते हैं, सुधार के बाद बनी नई व्यवस्था को पुरानी व्यवस्था से भी खराब है। यानी पुरानी व्यवस्था ही बेहतर थी कम से कम ऐसी गड़बड़ी तो नहीं होती थी ।हर क्षेत्र में कुछ लोग जो पुरानी व्यवस्था या जो व्यवस्था बनी हुई है उसी के पक्षधर इसलिए होते हैं कि पुरानी व्यवस्था में वह जैसा चाहे वैसा भ्रष्टाचार कर सकते हैं,वह पुरानी व्यवस्था में भ्रष्टाचार के आदी है और नई व्यवस्था में भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हो जाती है, इसलिए यथास्थितिवादी सुधार का विरोध करते हैं, हर क्षेत्र में नई तकनीक का विरोध करते हैं ताकि उनका भ्रष्टाचार का धंधा चलता रहे ।वह नहीं चाहते हैं कि भ्रष्टाचार कम होना चाहिए। इसलिए हर नई तकनीक का विरोध करते हैं क्योंकि तकनीक से भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम होती जाती है।

2014 के पहले कहा जाता था और यह सच भी था कि हम केंद्र से किसी आदमी को एक रुपए भेजते हैं तो उस आदमी तक एक रुपए नहीं 15 पैसे पहुंचते थे। यानी स्वीकार किया जाता था कि केंद्र से जो पैसा राज्यों के लोगों तक भेजा जाता है, उसमें 85 प्रतिशत भ्रष्टाचार होता है। सब मानते थे,स्वीकार करते थे लेकिन इस व्यवस्था को यथास्थितिवादी बदलने को तैयार नहीं थे, वह मानने को तैयार नहीं थे कि ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती है या सुधार हो सकता है कि अनिवार्य रूप से हो रहे 85 प्रतिशत भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। सब मानते थे कि यह संभव नहीं है कि केंद्र से एक रुपए राज्यों को भेजा जाए तो लोगों को एक रूपए ही मिले। सब मानते थे कि कोई उपाय नहीं है लेकिन नई तकनीक आने के बाद ऐसा आज संभव हुआ है कि केंद्र एक रुपए राज्य के लाखों के खाते में भेजे तो कुछ मिनट में रुपए उसके खाते में पहुंच जाता है। यह इसलिए संभव हुआ है कि तकनीक के कारण केंद्र व राज्य के बीच जो विभिन्न पदों पर बैठे हुए आदमी थे और 85 प्रतिशत भ्रष्टाचार करते थे,तकनीक के चलते उनकी जरूरत नहीं रही। यानी राज्य व केंद्र के बीच आदमियों की एक लंबी श्रृंखला है, वह जब तक है, भ्रष्टाचार को रोका नहीं जा सकता क्योंकि आदमी ही तो भ्रष्टाचार करता है।

किसी भी सिस्टम में जब तक आदमी है, भ्रष्टाचार की गुंजाइश तो बनी ही रहेगी। किसी सिस्टम में मान लो 100 आदमी हैं और इनमें 90 ईमानदार है और दस बेईमान हैं तो दस प्रतिशत भ्रष्टाचार तो होगा ही। कोई यह नहीं देखेगा कि 90 लोग ईमानदार है सब यही देखेंगे कि भ्रष्टाचार हो रहा है यानी सिस्टम ठीक नहीं है ।बुरी बात यह है कि ज्यादातर लोग 10 प्रतिशत भ्रष्टाचार की बात करते हैं 90 प्रतिशत ईमानदार लोगों की कोई बात नही करता। पेपर लीक यही दस प्रतिशत लोग करते हैं और 90 प्रतिशत लोग सिस्टम को अच्छा बनाए रखने का प्रयास करते हैं लेकिन उनकी कोशिश का कोई मतलब नहीं रह जाता। सब मान लेते हैं कि पूरा सिस्टम ही गलत है। इस आधार पर लोग यह कहने से नहीं चूकते हैं कि सुधार के बाद बनाया गया नया सिस्टम ठीक नहीं है। किसी भी तरह की परीक्षा के लिए बनाया गया सिस्टम ठीक नहीं है क्योंकि पेपर लीक हो रहा है, कई तरह की तकनीकी गड़बड़ी हो रही है।

यह बात तो सही है कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे बड़ी अव्यवस्था फैलती है, लाखों बच्चों,उनके परिजनों को कई तरह की परेशानी होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि नया सिस्टम ही खराब है। पुराना परीक्षा का सिस्टम ही ठीक था। आज का जो नया सिस्टम वह कई सुधारों का परिणाम है। यह हम भूल गए हैं कि एक वक्त था जब बोर्ड की परीक्षा नहीं होती थी,स्कूल की परीक्षा पास कर लेना काफी होता था, बाद में पांचवी, ग्यारहवीं, उसके बाद दसवीं, बारहवीं की बोर्ड की परीक्षा शुरू हुई यानी परीक्षा का एक सिस्टम बना, यह सिस्टम उस वक्त होने वाले भ्रष्टाचार होने के कारण ही बना था यानी योग्यता का एक पैमाना बनाया गया। राज्य स्तर पर बोर्ड होते थे तो राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार होने लगे। यानी जिस स्तर की परीक्षा होती थी,उस स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ। इसलिए आज केंद्र के स्तर पर जो परीक्षा की व्यवस्था है वह राज्य स्तर पर होने वाले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाया गया है।

पहले राज्य स्तर पर परीक्षा होती थी तो राज्य स्तर पर छात्र प्रभावित होते थे इसलिए हल्ला राज्य स्तर पर होता था। आज राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा हो रही है तो भ्रष्टाचार भी राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है। इससे पूरे देश में छात्र प्रभावित हो रहे हैं ।देश में मेहनतकर पास होने वाले छात्रों की संख्या निश्चित रूप से ज्यादा है, ज्यादातर छात्र व माता पिता चाहते हैं कि उनका बेटा मेहनत कर परीक्षा पास करे ।लेकिन कम संख्या में सही ऐसे छात्रों व माता पिता है जो चाहते हैं कि उनका बेटा बिना मेहनत के आसानी से परीक्षा पास कर ले, पेपर लीक इन्हीं लोगों के कारण होता है। यही लोग पेपर लीक लाखों रुपए देकर कराते हैं और पेपर लीक कराने के लाखों रुपए मिलते हैं ,इसलिए पेपर सेट करने वालों से लेकर पेपर केंद्रों में खोलनेवाला तक पैसे के लिए पेपर लीक करने तैयार हो जाते हैं। कोचिंग माफिया का इसमें बडा रोल होता है यानी पेपर लीक की मांग है तो पेपर लीक कराया जा रहा है। पेपर लीक रोकने के लिए भी सरकार को तकनीक का सहारा लेना पड़ेगा। पेपर लीक तकनीक के कारण आसान हो गया है तो पेपर लीक को तकनीक के जरिए ही रोकने का काम करना होगा।

विश्व पर्यावरण दिवस 2026 : हरित विकास, जल संरक्षण और जनभागीदारी से पर्यावरणीय समृद्धि की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़

डॉ. दानेश्वरी संभाकर, उपसंचालक जनसंपर्क

प्रकृति केवल हमारे जीवन का आधार नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और भविष्य की संरक्षक भी है। स्वच्छ वायु, निर्मल जल, घने वन और समृद्ध जैव विविधता किसी भी सभ्य समाज की अमूल्य धरोहर होते हैं। तेजी से बढ़ते शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव के इस दौर में पर्यावरण संरक्षण केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि मानव अस्तित्व की अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है। इसी उद्देश्य से प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो हमें प्रकृति के प्रति अपने दायित्वों का स्मरण कराता है।

प्राकृतिक संपदा से समृद्ध छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में शामिल है, जहां पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य के विशाल वन क्षेत्र, समृद्ध जैव विविधता और जल संसाधन इसकी पर्यावरणीय पहचान हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार हरित विकास, जल संरक्षण और जनभागीदारी को केंद्र में रखकर अनेक योजनाओं का सफल संचालन कर रही है।

हरियाली से समृद्धि की ओर

छत्तीसगढ़ में वृक्षारोपण को केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की आय से भी जोड़ा गया है। हरियाली प्रसार योजना और किसान वृक्ष मित्र योजना के माध्यम से किसानों को कृषि वानिकी के लिए पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं तथा उन्हें अपनी भूमि पर वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे एक ओर हरित क्षेत्र का विस्तार हो रहा है तो दूसरी ओर किसानों को दीर्घकालिक आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो रहा है।

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर संचालित एक पेड़ मां के नाम अभियान ने पर्यावरण संरक्षण को जनभावनाओं से जोड़ने का कार्य किया है। इस अभियान के माध्यम से लाखों नागरिक अपनी मां के सम्मान में पौधारोपण कर प्रकृति संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। यह पहल पर्यावरणीय जिम्मेदारी को सामाजिक आंदोलन का स्वरूप प्रदान कर रही है।

शहरों को मिल रही हरित पहचान

तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। इस दिशा में ऑक्सीवन योजना के तहत शहरों में ऑक्सीजन पार्क और हरित क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। वहीं पर्यावरण वानिकी योजना के माध्यम से सड़क किनारे वृक्षारोपण, पर्यावरण पार्कों का निर्माण तथा सार्वजनिक स्थलों का हरित विकास किया जा रहा है। ये प्रयास न केवल प्रदूषण नियंत्रण में सहायक हैं, बल्कि नागरिकों को बेहतर जीवन गुणवत्ता भी प्रदान कर रहे हैं।

जल संरक्षण बना जनआंदोलन

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को देखते हुए जल संरक्षण आज सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस दिशा में कई अभिनव पहलें की हैं। मोर गांव मोर पानी और मोर गांव मोर तरिया जैसे अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण की नई चेतना पैदा कर रहे हैं। परंपरागत तालाबों का पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन, चेक डैम निर्माण और जल पुनर्भरण संरचनाओं के विकास से भूजल स्तर में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं।

राज्य में भूजल एवं जल संरक्षण कार्यक्रमों के तहत जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन पर विशेष बल दिया जा रहा है। जल सुरक्षा की यह सोच आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य की नींव रख रही है।

नदियों और आद्रभूमियों का संरक्षण

प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने के लिए नदी तट वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत नदी किनारों पर बड़े पैमाने पर

पौधारोपण किया जा रहा है। इससे मिट्टी के कटाव पर नियंत्रण, भूजल संवर्धन और जैव विविधता संरक्षण में मदद मिल रही है।

इसी प्रकार आर्द्र भूमि (वेटलैंड) जलवायु अनुकूलन परियोजना के तहत महानदी जलग्रहण क्षेत्र में आद्रभूमियों के संरक्षण और पुनर्जीवन का कार्य किया जा रहा है। यह पहल जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और प्राकृतिक जल तंत्र को सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

नई पीढ़ी को पर्यावरण का प्रहरी बनाने की पहल

पर्यावरण संरक्षण की सफलता जन-जागरूकता और जनभागीदारी पर निर्भर करती है। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय हरित कोर योजना (नेशनल ग्रीन कॉर्प्स) तथा ईको-क्लब कार्यक्रमों के माध्यम से स्कूलों और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, जल संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण संबंधी कार्यक्रमों के जरिए बच्चों और युवाओं में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता विकसित की जा रही है।

पर्यावरण संरक्षण : सरकार और समाज की साझा जिम्मेदारी

पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी योजनाओं से संभव नहीं है। इसके लिए प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। एक पौधा लगाना, जल की बचत करना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना और स्वच्छता बनाए रखना ऐसे छोटे-छोटे कदम हैं जो बड़े परिवर्तन का आधार बन सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस हमें यह संदेश देता है कि विकास और पर्यावरण एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। छत्तीसगढ़ आज हरियाली, जल संरक्षण और जनभागीदारी आधारित विकास मॉडल के माध्यम से इसी संतुलित दृष्टिकोण को साकार कर रहा है। यदि हम सभी प्रकृति के प्रति अपने दायित्वों को समझें और पर्यावरण संरक्षण को जीवनशैली का हिस्सा बनाएं, तो आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ, हरित और सुरक्षित पृथ्वी सौंप सकेंगे। धरती हमें विरासत में नहीं मिली है, बल्कि हमने इसे आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है। इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना हम सभी का नैतिक दायित्व है।

वैश्विक पर्यावरण संकट : प्रकृति के बदलते मिजाज को लेकर गंभीरता जरूरी

ज्ञानेन्द्र रावत

पश्चिमी मॉडल पर आधारित विकास योजनाओं से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। कॉपीरेट दुनिया के स्वार्थ को बढ़ावा देने के चलते प्रदूषण बढ़ने से ग्लोबल वॉर्मिंग, जलस्रोतों व जंगलों का विनाश आदि समस्याएं बढ़ीं। जिनका असर जीवन व स्वास्थ्य पर हुआ। प्रकृति के उतार-चढ़ाव मानवता के लिए चेतावनी हैं। महात्मा गांधी ने वर्ष 1928 में ही उत्पादन और खपत के पश्चिमी मॉडल के चलते वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय असंतुलन की चेतावनी देते हुए कहा था—ईश्वर कभी नहीं चाहता कि भारत कभी पश्चिम की तरह औद्योगिकीकरण अपनाए। साथ ही कहा था कि एक छोटे से द्वीप साम्राज्य (इंग्लैंड) के आर्थिक साम्राज्यवाद ने आज दुनिया को जंजीरों से जकड़ रखा है। यदि तीस करोड़ की आबादी वाले देश ने ऐसा आर्थिक शोषण किया तो पूरी दुनिया टिड्डियों की तरह बेकार हो जाएगी।

गांधीजी का मानना था कि देश को आजादी के बाद गरीबी दूर करने और लोगों के सम्मानजनक जीवनयापन की दृष्टि से आर्थिक विकास करना ही होगा। ऐसे में भारत को अपने प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में कहीं अधिक जिम्मेदारी दिखानी होगी और पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाना होगा। दुखद है कि आजाद भारत की सरकारों ने गांधी के विचारों को पूरी तरह बिसरा दिया। परिणामस्वरूप, जहां मानव जीवन प्रभावित हुआ, वहीं संसाधनों पर कॉपीरेट घरानों के कब्जे से ग्रामीण और आदिवासी समाज बेदखली का शिकार हुआ। साथ ही औद्योगिक परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के कारण प्रदूषण की समस्या ने भयावह रूप ले लिया।

इस तबाही के विरोध में देश में चिपको, नमर्दा और मछुआरों के आंदोलन सामने आए। इसके उपरांत देश में पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना हुई और पारिस्थितिक नुकसान रोकने के लिए अनेक कानून बने। लेकिन सत्ता पर काबिज विभिन्न सरकारों ने समाज के व्यापक हित के बजाय निजी कॉपीरेट घरानों के हितों को सवीपरि मानकर उनके आगे झुकना उचित समझा। कॉपीरेट घरानों के निजी स्वार्थ के चलते प्रदूषित शहर, भयावह स्तर तक प्रदूषित वातावरण, मरती जीवनदायी नदियां, प्रदूषित जल, प्रदूषित वायु, गिरता भूजल स्तर, खत्म होते जलस्रोत व जंगल, प्रदूषित मिट्टी, बंजर होती जमीन आदि पर्यावरण विनाश और तबाही के स्पष्ट सबूत हैं। इसका सीधा असर मानव स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। इसके बावजूद यह सिलसिला बेरोकटोक जारी है।

वैश्विक स्तर पर देखें तो बीस वर्ष पहले हम सालाना आठ अरब मीट्रिक टन कार्बन वायुमंडल में छोड़ रहे थे, जिसका आंकड़ा बढ़कर आज डेढ़ गुणा से भी अधिक हो गया। इसके कारण धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। आज दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा जोरों पर है। प्रकृति का मिजाज बदल रहा है, और इसमें जलवायु परिवर्तन ने अहम भूमिका निभाई है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कायर्कारी निदेशक का कहना है कि दुनिया में ऊर्जा की जरूरत पूरी करने के लिए कोयला, तेल और गैस का अधिक इस्तेमाल हो रहा है। भारत के संदर्भ में ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन रोकने के भारत के प्रयास अभी भी नाकाफी हैं। भारत ने 2030 तक ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन की तीव्रता में 33-35 प्रतिशत तक कमी लाने का ऐलान किया था, लेकिन पेरिस समझौते के मुताबिक डेढ़ डिग्री के लक्ष्य के हिसाब से यह पर्याप्त नहीं है। देश को विभिन्न क्षेत्रों के लिए अपने उत्सर्जन लक्ष्य नए सिरे से तय करने की आवश्यकता है, अन्यथा 2095 तक धरती का तापमान चार डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा।

यदि कार्बन उत्सर्जन में कमी न आई तो जल संकट बढ़ेगा, बीमारियां बढ़ेंगी, खाद्यान्न उत्पादन में कमी आएगी, ध्रुवों की बर्फ तेज गति से पिघलेगी, समुद्र का जलस्तर तेजी से बढ़ेगा। नतीजन, दुनिया के कई देश पानी में डूब सकते हैं। समुद्र किनारे बसे सैकड़ों शहर-महानगर जलमग्न होंगे, और लगभग 20 लाख से अधिक प्रजातियां सदा-सदा के लिए खत्म हो जाएंगी। वहीं, सदियों से जीवन के आधार रहे खाद्य पदार्थों के पोषक तत्व कम हो जाएंगे। विशेष रूप से बी-1, बी-2, बी-5 और बी-8 जैसी विटामिनों में कमी आएगी। बीमारियों से बचाने वाले जैव रसायनों में भी कमी आने की संभावना है। यदि पृथ्वी का तापमान और अधिक बढ़ गया तो धरती का एक-चौथाई हिस्सा रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। वहीं 20-30 प्रतिशत हिस्सा सूखे का शिकार होगा। नतीजतन, दुनियाभर में लगभग 150 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित होंगे। जंगलों में आग की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि होगी। इसका सबसे ज्यादा असर भारत समेत दक्षिण-पूर्व एशिया, दक्षिण यूरोप, मध्य अमेरिका और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया पर पड़ेगा।

चौंकाने वाली बात यह कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते पहले बीते चार दशकों में कम हो चुकी उवर्रा शक्ति वाली जमीन की सेहत बिगड़ने की दर अब सौ गुणा बढ़ गई है। उस हालत में भविष्य में दुनिया की आबादी का पेट भरने के लिए अन्य संसाधनों पर निर्भर होना पड़ेगा। आने वाले 24 वर्षो में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, मध्यपूर्व और उत्तरी अफ्रीका को इस चुनौती का भीषण सामना करना पड़ेगा। इन क्षेत्रों में सदी के अंत तक तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाएगा। इसका असर खाद्यान्न, पेयजल और प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ेगा। नतीजन आम आदमी का जीवन मुहाल हो जाएगा।

प्रकृति के सारे उतार-चढ़ाव मानवता को संभलने के लिए चेतावनी हैं। पर्यावरण तेजी से बदल रहा है। लेकिन हम लोग इन्हें समझने और गंभीरता से लेने के बजाय नजरअंदाज कर रहे हैं। जरूरत इस दिशा में ईमानदारी से प्रयास करने की है मसलन, जीवनशैली में बदलाव व प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाना। ताकि पूरी पृथ्वी और मानवता के साथ-साथ इस ग्रह पर रहने वाले तमाम जीव-जंतुओं को विनाश से बचाया जा सके।

अब न्याय होगा ऑनलाइन : छग की राजस्व ई-कोर्ट परियोजना बनी डिजिटल सुशासन की नई मिसाल

विष्णु प्रसाद वर्मा, सहायक संचालक रायपुर

भारत तेजी से डिजिटल प्रशासन की ओर बढ़ रहा है और इसी दिशा में छत्तीसगढ़ ने राजस्व प्रशासन को आधुनिक, पारदर्शी और आमजन के लिए सहज बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की है। राज्य सरकार द्वारा लागू की गई राजस्व ई-कोर्ट परियोजना अब केवल एक तकनीकी व्यवस्था नहीं रह गई है, बल्कि यह ग्रामीण और शहरी नागरिकों के लिए न्याय प्राप्ति की प्रक्रिया को सरल, त्वरित और भरोसेमंद बनाने वाला प्रभावशाली माध्यम बन चुकी है।

वर्षों तक राजस्व मामलों में आम लोगों को तहसील, एसडीएम कार्यालय और कलेक्टर कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, फौती प्रकरण, खाता सुधार या भूमि विवाद जैसे मामलों में पेशी की तारीख जानने, आदेश की प्रति लेने या केस की स्थिति समझने में समय, धन और ऊर्जा तीनों की भारी खपत होती थी। कई बार बिचौलियों और भ्रष्टाचार का सामना भी करना पड़ता था। लेकिन अब वही पूरी प्रक्रिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है।

छत्तीसगढ़ की ई-कोर्ट परियोजना ने राजस्व न्यायालयों की पारंपरिक कार्यप्रणाली को बदलकर उसे पेपरलेस, स्मार्ट और जनकेंद्रित बना दिया है। नायब तहसीलदार से लेकर कलेक्टर और राजस्व मंडल तक की न्यायिक प्रक्रिया अब ऑनलाइन संचालित हो रही है। इससे न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ी है, बल्कि आम नागरिकों का भरोसा भी मजबूत हुआ है।

ई-कोर्ट व्यवस्था एक प्रभावी समाधान- मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

मुख्यमंत्री ने राजस्व ई-कोर्ट परियोजना को सुशासन और डिजिटल प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा है कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और जनता के लिए सुलभ बनाना है। उन्होंने कहा कि तकनीक का उपयोग तभी सार्थक माना जाएगा, जब उसका सीधा लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

राजस्व मामलों में वर्षों से चली आ रही जटिलताओं को समाप्त करने के लिए ई-कोर्ट व्यवस्था एक प्रभावी समाधान बनकर सामने आई है। अब नागरिकों को छोटी-छोटी जानकारियों के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार न्याय प्रक्रिया को लोगों के मोबाइल तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ने से भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका स्वतः समाप्त होगी तथा आम लोगों का शासन-प्रशासन पर विश्वास और मजबूत होगा। मुख्यमंत्री के अनुसार, ई-गवर्नेंस केवल तकनीक नहीं, बल्कि जनता को सम्मानपूर्वक और समयबद्ध सेवाएं देने का माध्यम है।

पारदर्शिता और जवाबदेही की नई व्यवस्था

ई-कोर्ट प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें आवेदन प्राप्त होते ही उसका ऑनलाइन पंजीकरण किया जाता है और तत्काल डिजिटल पावती जारी होती है। इससे आवेदक को यह भरोसा मिल जाता है कि उसका आवेदन रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है और अब उसे किसी कर्मचारी या दलाल के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा।

इसके बाद की पूरी प्रक्रियाकृजैसे नोटिस जारी करना, इश्तहार प्रकाशित करना, पक्षकारों को सूचना भेजना, सुनवाई की तारीख तय करना और अंतिम आदेश पारित करना सभी ऑनलाइन दर्ज होते हैं। प्रत्येक कार्रवाई डिजिटल रिकॉर्ड में सुरक्षित रहती है, जिससे किसी भी स्तर पर हेरफेर की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है।

ई-कोर्ट पोर्टल के माध्यम से नागरिक अपने मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे यह देख सकते हैं कि उनके मामले में पिछली तारीख पर क्या कायर्वाही हुई, अगली पेशी कब है और आदेश जारी हुआ है या नहीं। इससे न्यायालयों के बाहर लगने वाली भीड़ और अनावश्यक भागदौड़ में उल्लेखनीय कमी आई है।

किसानों और ग्रामीण नागरिकों के लिए बड़ी राहत

राजस्व मामलों का सबसे अधिक प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों और भू-स्वामियों पर पड़ता है। पहले किसानों को एक छोटी सी जानकारी के लिए भी पूरे दिन का समय निकालकर तहसील मुख्यालय जाना पड़ता था। कई बार केवल अगली तारीख जानने में ही मजदूरी और किराए का नुकसान हो जाता था।

अब ई-कोर्ट व्यवस्था ने यह परेशानी काफी हद तक समाप्त कर दी है। किसान अपने गांव के लोक सेवा केंद्र, चॉइस सेंटर या मोबाइल फोन के माध्यम से ही अपने प्रकरण की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे समय और धन दोनों की बचत हो रही है तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अप्रत्यक्ष रूप से मजबूती मिल रही है।

डिजिटल न्याय व्यवस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन के प्रति विश्वास को भी बढ़ाया है। जब लोगों को अपने आवेदन की ऑनलाइन पावती और हर कारर्वाई की जानकारी समय पर मिलने लगती है, तो पारदर्शिता स्वतः स्थापित होती है।

विवादित जमीनों की जानकारी अब सार्वजनिक

ई-कोर्ट परियोजना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि विचाराधीन भूमि विवादों की जानकारी अब ऑनलाइन उपलब्ध रहती है। इससे जमीन खरीदने वाले लोग पहले ही जांच कर सकते हैं कि संबंधित खसरा नंबर पर कोई विवाद या न्यायालयीन प्रकरण लंबित तो नहीं है। यह व्यवस्था फर्जीवाड़े, अवैध बिक्री और धोखाधड़ी रोकने में अत्यंत प्रभावी साबित हो रही है। पहले कई लोग विवादित भूमि खरीदकर वर्षों तक न्यायालयों के चक्कर काटते रहते थे, लेकिन अब पारदर्शी ऑनलाइन रिकॉर्ड के कारण ऐसी घटनाओं में कमी आई है।

तकनीक के सहारे मजबूत हुआ प्रशासन

राजस्व ई-कोर्ट प्रणाली के सफल संचालन के लिए प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में कंप्यूटर, डिजिटल रिकॉर्ड प्रणाली और हाई-स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इससे न्यायालयों के कार्य निष्पादन की गति बढ़ी है और अधिकारियों की जवाबदेही भी तय हुई है।

डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित सर्वर में संग्रहीत होने से अब फाइलों के गुम होने, फटने या रिकॉर्ड में छेड़छाड़ जैसी समस्याएं लगभग समाप्त हो चुकी हैं। प्रशासनिक निगरानी भी आसान हुई है क्योंकि उच्च अधिकारी किसी भी न्यायालय की कार्यवाही ऑनलाइन मॉनिटर कर सकते हैं।

मोबाइल में कोर्ट की दिशा में बड़ा कदम

छत्तीसगढ़ की यह पहल वास्तव में ङ्कमोबाइल में कोर्टङ्क की अवधारणा को साकार करती दिखाई देती है। अब नागरिकों को केवल जानकारी लेने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। आदेश की कॉपी डाउनलोड करने से लेकर केस की स्थिति जानने तक अधिकांश सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

ई-कोर्ट व्यवस्था ने यह साबित किया है कि यदि प्रशासनिक इच्छाशक्ति और तकनीक का सही समन्वय हो, तो शासन को वास्तव में जनसुलभ बनाया जा सकता है। यह पहल ई-गवर्नेंस को स्मार्ट गवर्नेंस में बदलने का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरी है।

सुशासन की दिशा में प्रभावी पहल

छत्तीसगढ़ सरकार की राजस्व ई-कोर्ट परियोजना केवल तकनीकी सुधार नहीं, बल्कि आम जनता को न्याय व्यवस्था से सीधे जोड़ने का अभिनव प्रयास है। इसने प्रशासन और नागरिकों के बीच की दूरी कम की है तथा न्यायिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, त्वरित और भरोसेमंद बनाया है।

स्वास्थ्य सेवाओं की नई पहचान बना जिला चिकित्सालय

नई दृष्टिबिंदु / मुंगेली

आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं और मरीज-केंद्रित उपचार के कारण जिला चिकित्सालय मुंगेली अब न केवल जिले बल्कि आसपास के जिलों और अन्य राज्यों के मरीजों के लिए भी भरोसे का केंद्र बनता जा रहा है। कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देश, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शीला साहा, जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉ. गिरीश कुर्रे के मार्गदर्शन तथा सिविल सर्जन डॉ. एम.के. राय के प्रयासों से जिला अस्पताल का फिजियोथेरेपी विभाग वर्षों पुराने दर्द और शारीरिक अक्षमता से जूझ रहे मरीजों के जीवन में नई उम्मीद जगा रहा है। मुंगेली के गोल बाजार निवासी नकुल साहू, जो लकवा होने के बाद लगभग एक वर्ष तक चलने-फिरने में असमर्थ थे, आज 09 माह की नियमित फिजियोथेरेपी के बाद सामान्य जीवन जी रहे हैं। उनकी यह सफलता उन सैकड़ों मरीजों के लिए प्रेरणा बन गई है, जो गंभीर बीमारी या चोट के बाद निराश हो चुके थे।

इसी तरह मध्यप्रदेश के शहडोल निवासी आतिश दास, जो पिछले तीन वर्षों से बिस्तर पर थे और चलने की उम्मीद छोड़ चुके थे, आज जिला चिकित्सालय की फिजियोथेरेपी सेवाओं के कारण अपने पैरों पर खड़े होकर सामान्य जीवन जी रहे हैं। वहीं मुंगेली की सरिता बाजपेयी, जो एक वर्ष तक कमर झुकाकर चलने को मजबूर थीं, अब सहज रूप से चल-फिर रही हैं। लोरमी के सारथु राम, जो 5-6 वर्षो से कंधे के असहनीय दर्द से परेशान थे, तथा बलौदाबाजार के रमेश सिंह, जो 08 वर्षो से कमर दर्द से जूझ रहे थे, उन्हें भी फिजियोथेरेपी उपचार से राहत मिली है। इसके अलावा मुंगेली की निशा यादव, जो लिगामेंट ऑपरेशन के बाद घुटनों के दर्द और जकड़न से परेशान थीं, अब सामान्य गतिविधियां करने में सक्षम हैं।

जिला चिकित्सालय का फिजियोथेरेपी विभाग वतर्मान में अत्याधुनिक मशीनों और आधुनिक उपचार पद्धतियों से सुसज्जित है। यहां सामान्य फिजियोथेरेपी के साथ-साथ एडवांस एक्यूपंक्चर थेरेपी, एडवांस गेट थेरेपी, फायर कपिंग, नॉर्मल कपिंग, फुल बॉडी रिलैक्सेशन थेरेपी, लेजर थेरेपी और पीआरपी थेरेपी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सिविल सर्जन डॉ. एम.के. राय ने बताया कि फिजियोथेरेपी के प्रति लोगों की जागरूकता लगातार बढ़ रही है और प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं।

ऑफिस में चाहिए स्टाइलिश लुक तो ट्राई करें ये लेटेस्ट डिजाइन वाले पेंट-सूट

अगर आप ऑफिस गोइंग वुमन हैं तो आप ऑफिस में ये लेटेस्ट डिजाइन वाले पेंट-सूट वियर कर सकती हैं और इस तरह के पेंट-सूट में आप स्टाइलिश नजर आएंगी।

ऑफिस गोइंग वुमन ऑफिस में ऐसा आउटफिट पहनना पसंद करती हैं जिसमें वो कंफर्टेबल रहे साथ ही इस तरह के आउटफिट में वो स्टाइलिश भी नजर आए। अगर आप भी न्यू और स्टाइलिश लुक चाहती हैं तो आप ये पेंट-सूट वियर कर सकती हैं। इस आर्टिकल में हम आपको कुछ लेटेस्ट डिजाइन वाले पेंट-सूट दिखाएंगे जिन्हें आप ऑफिस में वियर कर सकती हैं।

कांथा वर्क पेंट-सूट

अगर आप स्टाइलिश के साथ-साथ रॉयल लुक चाहती हैं तो आप इस तरह का कांथा वर्क पेंट-सूट वियर कर सकती हैं। यह पर्पल कलर का पेंट-सूट पर कांथा वर्क किया हुआ है और इस वजह से ये आउटफिट देखने में काफी खूबसूरत नजर आ रहा है। इस पेंट-सूट के साथ आप ब्लैक कलर की हील्स पहन सकती हैं जो इस आउटफिट के साथ परफेक्ट रहेंगे। इस तरह का आउटफिट आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा साथ ही ऑनलाइन भी आप इस तरह के पेंट-सूट 700-800 तक कीमत में खरीद सकती हैं।

कॉटन पैंट सूट

जो महिलाएं लाइट कलर की तलाश में होती हैं और कुछ नया ट्राई करने का सोच रही हैं तो आप इस तरह काकॉटन पैंट सूट वियर कर सकती हैं। यह पेंट सूट कॉटन में है और समर सीजन में पहनने के लिए ये सूट बेस्ट हैं। ऑफिस में कोई इवेंट हो या कोई पार्टी आप इस तरह का पैंट सूट इन मौकों पर भी वियर कर सकती हैं। इस ड्रेस के साथ स्टाइलिश लुक के लिए जुती पहन सकती हैं साथ ही में मिनिमल ज्वेलरी भी वियर कर सकती हैं। यह कॉटन पैंट सूट आप बाजार से ले सकती हैं या फिर ऑनलाइन भी खरीद सकती हैं। यह पैंट सूट आपको 1000 तक की कीमत में मिल जायेगा।

वोवन पैंट सूट

सिंपल लुक के लिए आप इस तरह का वोवन फैब्रिक वाला पैंट सूट पहन सकती हैं। इस तरह का सूट में जहां आपका लुक स्टाइलिश लगेगा तो वहीं इस सूट में आप भीड़ से भी अलग नजर आएंगी। इस तरह

सूट के साथ आप प्लैट्स पहन सकती हैं साथ में नेकलेस वियर कर सकती हैं। यह वोवन पैंट सूट आप मार्केट से खरीद 500 तक की कीमत में मिल जाएगा साथ ही ऑनलाइन भी आप इसी कीमत में ये पैंट सूट खरीद सकती है।

पुरानी चीजों को फेंकने के जगह इस तरह से करें डेकोरेट

हम सभी घरों में अक्सर पुरानी चीजें रखे-रखें खराब हो जाती है। इसके पीछे का कारण या तो उनका काम में यूजफुल न होना होता है। इसके अलावा हम सभी कई चीजों को इस लिए भी नहीं फेंक पाते हैं क्योंकि उससे हमारी यादें जुड़ी होती है। ऐसा कुछ हाल घर में मौजूद फर्नीचर के साथ होता है।

फर्नीचर जैसे बेड, मेज और अलमारी का कलर निकल जाने के कारण ये पुराने और भद्दे से लगते हैं। अगर आपके घर में भी कुछ पुराने फर्नीचर रखें हैं। वह देखने में खराब लगने लगे हैं, तो बता दें कि आप इसका मेकओवर इसे नया जैसा बना सकते हैं. इसके लिए आपको केवल सामान की जरूरत पड़ेगी।

इस तरह से फर्नीचर को करें डेकोरेट

अगर आप थोड़े क्रिएटिव हैं और आपको कुछ नया करने में अच्छा लगता है। इस स्किल का उपयोग कर आप कम पैसे सामान को नया बना सकते हैं। अगर आपको ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बाजार में मिलने वाले स्टिकर की मदद से भी सूटकेस, अलमारी और बेड को सजा सकती हैं।

फर्नीचर को सजाने के लिए जरूरी सामान

- कपड़ा
- पानी
- विनेगर
- एक बर्तन
- पेंट रोलर ब्रश
- पेंट कलर
- ब्रश
- स्क्रब
- डिजाइन स्टिकर
- व्हाइट टेप

सामान को सजाने का तरीका

- घर में मौजूद पुराने फर्नीचर मेज, कुर्सी, बेड और अलमारी इत्यादि जिसे आप नया बनाना चाहते हैं। उसे निकाल कर अलग कर लें।
- एक बर्तन में पानी लें उसमें विनेगर मिलाकर अच्छे से मिक्स करें। अब इस पानी की मदद से फर्नीचर को एक-एक करके साफ कर लें।
- साफ करने के बाद सामान को हल्की धूप में सुखाने के लिए रख दें।
- इसके बाद आप पेंट को निकाल कर फर्नीचर पर पहले बेस तैयार करें।
- बेस तैयार करने के बाद आप अपने मनपसंद रंग की मदद से इन्हें रोलर ब्रश की मदद से एक से दो कोट करें।
- आप चाहें तो फर्नीचर के ऊपर कलर की मदद से डिजाइन भी क्रिएट कर सकते हैं।
- बारीक डिजाइन बनाने के लिए आप बाजार में मिलने वाले डिजाइन स्टिकर की भी मदद ले सकते हैं।

कम समय में ऐसे करें बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट

अगर आप इस बार अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी को घर पर ही सेलिब्रेट करना चाहती हैं और इसकी तैयारी के लिए आपके पास समय कम है, तो यहां से आइडिया लेकर आप इंतजाम कर सकते हैं।

बर्थडे का दिन हर किसी के लिए बेहद खास होता है। कई लोग इसे बड़े होटल या फिर रेस्टोरेंट में जाकर सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग घर पर ही शानदार तरीके से फैमिली के साथ बर्थडे मनाते हैं। ऐसे में अगर आप भी इस बार अपने बच्चे का बर्थडे पार्टी घर पर ही सेलिब्रेट करने का सोच रहे हैं और आपके पास इंतजाम करने के लिए समय कम है, तो इस आर्टिकल की मदद ले सकते हैं। यहां हम आपको कुछ ऐसे शानदार टिप्स बताने वाले हैं, जिससे आप अपने बच्चे का जन्मदिन यादगार बना सकते हैं। कम समय में घर पर बच्चे की बर्थडे पार्टी कैसे मनाएं?

थीम चुनकर करें डेकोरेट

एक थीम चुनने से आपको सजावट, भोजन और गतिविधियों को चुनने में आसानी होगी। यह आपके बच्चे की पसंद की कोई भी चीज हो सकती है, जैसे कि कोई सुपरहीरो, कार्टून कैरेक्टर, या कुछ और भी, जो आपके बच्चे को पसंद हो, उसके अनुसार आप डेकोरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा, यदि आपके पास कम समय है, तो बहुत अधिक सजावट करने से बचें।

DIY तरीके से करें सजावट

अक्सर मन में सवाल आता है कि बर्थडे पर कैसे सजाएं रूम? तो आपको बता दें, आप इसके लिए क्रएटिविटी भी दिखा सकते हैं। पैसे और बाजार जाने का समय बचाने के लिए आप DIY तरीके से सजावट कर सकते हैं। आप पेपर फैन, बैनर और सेंटरपीस बना सकते हैं या फिर पिछली बार का घर में रखा हो, तो उसे भी दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं।

भोजन की व्यवस्था ऐसे करें

आसान और स्वादिष्ट भोजन बनाने का प्लान करें, ताकि आपके समय की बचत हो। पार्टी में ऐसे भोजन बनाएं, जो बच्चों को पसंद भी हो और जल्दी भी बन जाते हों। ऐसे में, आप सैंडविच, फिंगर फूड, पिज्जा या केक का इंतजाम कर सकते हैं। घर का

बना भोजन हेल्दी होने के साथ-साथ पैसे भी बचाएंगे। इसके अलावा, आप चाहें तो बच्चों के लिए कुकीज, कपकेक या स्नैक्स बना सकते हैं। साथ ही, जूस, पानी और सोडा जैसे कुछ सिंपल और टेस्टी ड्रिंक को भी आप रख सकते हैं।

फोटो बूथ बनाएं

बर्थडे पार्टी को यादगार बनाने के लिए आप घर पर छोटे-छोटे सेल्फी और फोटो लेने के लिए आप घर के किसी कोने में शानदार फोटो बूथ तैयार कर सकते हैं। इसे बनाने में आप इंटरनेट या बच्चों से भी कई क्रिएटिव आइडियाज ले सकते हैं।

बच्चों के लिए गेम का करें इंतजाम

बच्चों को व्यस्त रखने और उनके बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए आप कुछ पार्टी गेम का इंतजाम कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा डांस करने का शौक रखता है, तो घर में स्पीकर की व्यवस्था आप कर सकते हैं।

बर्थडे पार्टी को कम बजट में करना है प्लान तो ये टिप्स आएंगे काम

हम सभी साल में एक बार बर्थडे मनाते हैं। ना सिर्फ अपना बल्कि अपने करीबियों के बर्थडे पर भी हम पार्टी करते हैं। अगर आप भी अपने पति, पिता, बच्चों या किसी के भी बर्थडे पर पार्टी प्लान कर रही हैं तो कुछ टिप्स आपकी मदद कर सकते हैं। दरअसल आजकल महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसे में हम सभी अपने खर्च को कम से कम करना चाहते हैं। चलिए इस आर्टिकल में जानिए कि आखिर आप कम से कम खर्च में बर्थडे प्लान कैसे कर सकते हैं।

होटल की जगह घर या छत पर करें पार्टी

होटल या किसी हॉल को बुक करने पर एक साथ मोटी रकम देने पड़ती है। ऐसे में सही यही रहेगा कि आप घर या छत को खुद डेकोरेट करके पार्टी रखें। अगर आप छोटे बच्चे के लिए पार्टी रख रहे हैं को बलून, कार, बार्बी जैसी चीजों का इस्तेमाल करें। वहीं अगर पार्टी किसी बड़े के बर्थडे की है तो आप लाइटिंग और कैंडल लगाएं।

केक खरीदते वक्त रखें इन बातों का ध्यान

केक आप चाहे घर पर भी बना सकते हैं लेकिन हर किसी को केक बनाना नहीं आता है। ऐसे लोग केक खरीदते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखें। जैसे किस फ्लेवर का हो, कौनसी बेकरी डिस्काउंट दे रही है, ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है या ऑफलाइन और कोई कूपन लगा या नहीं आदि।

कोई स्पेशल थीम रखें

बर्थडे पार्टी को थोड़ा स्पेशल बनाने के लिए थीम रख सकते हैं। आजकल थीम बर्थडे पार्टी काफी ट्रेंड में भी हैं। इसके लिए आपको बस थीम चुननी है और उसी के मुताबिक डेकोरेशन करनी है।

ऑनलाइन मंगवाए गिफ्ट

बर्थडे पार्टी के दौरान हम सभी जिसका जन्मदिन होता है उसे गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट खरीदने के लिए ऑफलाइन के बजाए ऑफलाइन शॉपिंग प्लेटफार्म बेस्ट हैं। यहां से आप कम से कम खर्च में रिटर्न गिफ्ट भी मंगवा सकते हैं।

गर्मियों में पौधों को भी होती है ठंडक की जरूरत, इस 1 घोल से दूर करें प्लांट्स का डिहाइड्रेशन

बहुत कम लोग जानते है कि गर्मियों में इंसानों की ही तरह पौधों को भी डिहाइड्रेशन हो जाती है। ऐसे में पानी देने से भी पौधे हेल्दी और हरे-भरे नहीं रहते। आइए जानें, गर्मियों में पौधों को हाइड्रेट रखने के लिए कौन-सी खाद डालें?

गर्मियों में लोग अपनी सेहत का खूब ख्याल रखते हैं। पानी और लिक्विड डाइट को बढ़ा देते हैं, ताकि उन्हें भीषण गर्मी के कारण डिहाइड्रेशन ना हो जाए। शरीर का हेल्दी रखने के लिए लोग गर्मियों में न जाने क्या-क्या नहीं करते, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिस तरह से इंसानों को हाइड्रेट रहना होता है, उसी तरह पौधों को भी इसकी जरूरत होती है। गर्मी के इस मौसम में पौधों को भी डिहाइड्रेशन हो सकती है। ऐसे में उनका भी ख्याल रखना जरूरी हो जाता है। गर्मी में आपकी ही तरह आपके पौधों को भी ठंडाई की जरूरत पड़ती है। ऐसे में केवल पानी देने से काम नहीं चल पाता। पौधों को डिहाइड्रेशन की समस्या से बचाने के लिए आप घर पर ही एक ठंडी खाद बना सकते हैं। इससे पौधा हेल्दी और हाइड्रेट रहेगा।

एलोवेरा से तैयार करें खाद

पौधों को ठंडक देने वाली खाद बनाने के लिए आपको एलोवेरा की जरूरत होगी। एलोवेरा हर गार्डनर के बगीचे में जरूर होता है। इस खाद को तैयार करने के लिए एलोवेरा को काटकर उसके छोटे-छोटे टुकड़े कर लें। खराब एलोवेरा के हिस्सों को काटकर अलग कर लें। इसके लिए हेल्दी पत्तों का ही इस्तेमाल करें। अब एलोवेरा के टुकड़ों को पीसकर पानी में मिला लें। इसे एक बड़ी प्लास्टिक की बाल्टी में डालकर 3 दिनों के लिए ढककर साइड में रख दें। इस तरह से आपकी ठंडी खाद बनकर तैयार हो जाएगी।

एलोवेरा की खाद कैसे इस्तेमाल करें?

पौधों को हाइड्रेट करने वाली एलोवेरा की ठंडी खाद को तैयार होने के बाद कुछ देर अच्छे से मिक्स करें। अब इस घोल में उसका दोगुना पानी और मिला लें। इसे डाइल्यूट करना जरूरी है। अब आप अपने पौधों को गर्मियों में भी हरा-भरा रखने के लिए इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पौधे भीषण गर्मी में भी खिले रहेंगे।

ऐसे रखें पौधों का ख्याल

अगर आपके पैस एलोवेरा का पौधा नहीं है, तो आप पौधों को ठंडा रखने वाली खाद बनाने के लिए एक टेबल स्पून एलोवेरा जेल को पानी में मिलाकर गमले में डाल सकते हैं। इससे भी पौधों को हेल्दी रखने में मदद मिलेगी।

तकनीक और इनोवेशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन
बीटेक ईसीई

टेक और डिजिटल के बदलते युग में जॉब मार्केट में प्रोफेशनल्स की डिमांड भी बदलती जा रही है। आईटी सेक्टर के साथ-साथ लगभग सभी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर्स को अच्छे खासे पैकेज पर हायर किया जा रहा है, यही वजह है कि कॉलेज प्लेसमेंट सेशन में भी बीटेक ईसीई डिग्री वालों का प्लेसमेंट पैकेज सबसे तगड़ा मिलने लगा है। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कोर्स आज के टेक और डिजिटल युग में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। बदलते जॉब मार्केट में कंपनियों को ऐसे प्रोफेशनल्स की जरूरत है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझते हों। आईटी सेक्टर से लेकर ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम और हेल्थकेयर तक में ईसीई इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ी है। यही कारण है कि कॉलेज प्लेसमेंट के दौरान बीटेक ईसीई स्टूडेंट्स को हाई सैलरी पैकेज मिल रहे हैं। तकनीकी ज्ञान और मल्टी-डोमेन स्किल्स के चलते ये ग्रेजुएट्स इंडस्ट्री के लिए वैल्यूएबल एसेट बन चुके हैं।

बीटेक ईसीई कोर्स क्या है?

बीटेक ईसीई का पूरा नाम बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, जो चार वर्षीय ग्रेजुएशन लेवल का प्रोग्राम है। बीटेक ईसीई छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और डिवाइस कम्युनिकेशन, डिजाइन, निर्माण और रखरखाव के बारे में डिटेल जानकारी दी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डेटा और सिग्नल को अलग-अलग माध्यमों से भेजने की तकनीक सीखी जाती है। यह कोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग दोनों का मेल है, जो हार्डवेयर और नेटवर्किंग में स्किल देता है। यह फील्ड 5जी, सैटेलाइट, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन जैसी नई तकनीकों में करियर के अच्छे मौके देती है।

नौकरी पाने के मौके

बीटेक ईसीई में इलेक्ट्रॉनिक्स का परिचय, सिग्नल और सिस्टम, एनालॉग संचार, नेटवर्क सिस्टम, माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रोकंट्रोलर, नियंत्रण प्रणाली आदि जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। ये कोर्स टेक्नोलॉजी की नॉलेज देता है। इस कोर्स के बाद करियर के बहुत सारे ऑप्शन होते है जैसे की आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बन सकते है।

कौन कर सकता है ये कोर्स?

बीटेक ईसीई में एडमिशन लेने के लिए छात्र को 12वीं कक्षा पास होना जरूरी है। 12वीं में फिजिक्स, कैमिस्ट्री और मैथ्स विषय होना अनिवार्य है। छात्रों को 12वीं में कम से कम 50% से 60% अंक लाने होते हैं। अलग-अलग कॉलेजों में अंकों की जरूरत थोड़ी अलग हो सकती है। आरक्षित वर्ग को कुछ छूट मिल सकती है।

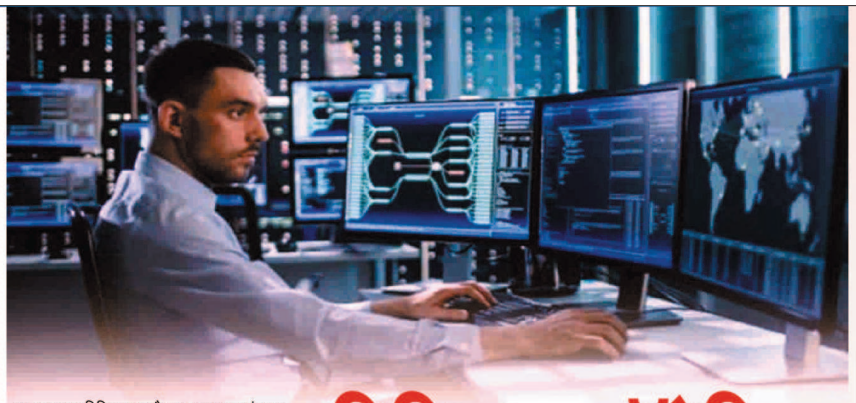

क्या आप स्क्रीन के पीछे से सच उजागर करना चाहते हैं? डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनकर आप साइबर अपराधों का पर्दाफाश कर सकते हैं. यह वो प्रोफेशन है जहां तकनीक, सस्पेंस और न्याय साथ चलते हैं–एक ऐसा करियर जो हर दिन एक नई कहानी बनाता है.

डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनकर
साइबर अपराधों का करें पर्दाफाश

आज का युग डिजिटल का है. हर काम अब कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट या क्लाउड के जरिए हो रहा है–चाहे बैंकिंग हो, ऑफिस वर्क, पढ़ाई या सोशल मीडिया. लेकिन जिस तेजी से डिजिटल तकनीक ने जिंदगी आसान की है, उतनी ही तेजी से बढ़े हैं डिजिटल अपराध. हैकिंग, डेटा चोरी, ऑनलाइन फॉड, साइबर बुलिंग जैसे मामलों की बाढ़ आ गई है. ऐसे में इन अपराधों की तह तक जाने और सच्चाई सामने लाने का काम करते हैं–डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स. इन्हें अक्सर स्क्रीन के पीछे का जासूस या डिजिटल डेटा डिटेक्टिव भी कहा जाता है. इनकी पहचान न तो वर्दी से होती है, न ही किसी हथियार से, बल्कि इनका सबसे बड़ा हथियार होता है – तकनीक की गहरी समझ और डिजिटल साक्ष्य जुटाने की कला.

डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट कौन होता है?

डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट वह प्रोफेशनल होता है जो कंप्यूटर, मोबाइल, हार्ड ड्राइव, ईमेल, सोशल मीडिया या क्लाउड जैसे डिजिटल स्रोतों से डिलीट या छिपाई गई जानकारी को रिकवर करता है और उसे कानूनी सबूत के रूप में पेश करता है.

अगर किसी ने ऑनलाइन बैंक फॉड किया है, या किसी अपराधी ने मोबाइल से सबूत मिटाने की कोशिश की है, तो ऐसे मामलों में यह एक्सपर्ट उन मिटाए गए डेटा को फिर से खोज निकालता है. ये कोर्ट में पेश करने योग्य फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार करते हैं, ताकि अपराधी को सजा मिल सके.

क्या होता है इनका काम?

डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट का काम बेहद पेचीदा और संवेदनशील होता है. उन्हें हर बिट और बाइट को सबूत में बदलना होता है. इनके काम में शामिल होते हैं –

- डिलीट हुए डेटा, ईमेल या कॉल रिकॉर्ड को रिकवर करना
- वायरस या मैलवेयर के जरिए की गई छेड़छाड़ का पता लगाना
- कंप्यूटर या मोबाइल में छिपाई गई फाइलों को ट्रेस करना
- साइबर क्राइम, बैंक फॉड, हैकिंग की जांच करना
- डिजिटल सबूतों की वैधानिक रिपोर्ट तैयार करना
- कोर्ट और लॉ एजेंसियों को केस में तकनीकी सपोर्ट देना
- इन एक्सपर्ट्स को कई बार सीबीआई, ईडी, क्राइम ब्रांच, या साइबर क्राइम सेल के साथ काम करने का मौका मिलता है. इसके अलावा कई बार निजी कंपनियां और बैंक भी इन्हें साइबर सुरक्षा के लिए हायर करते हैं.

क्या करें पढ़ाई?

डिजिटल फॉरेंसिक्स का प्रोफेशन बनने के लिए साइंस या टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड जरूरी होता है, लेकिन अब लॉ और क्रिमिनोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए भी इसमें करियर की राह खुल चुकी है.

कहां मिलती है नौकरी?

जैसे-जैसे डिजिटल क्राइम बढ़ रहा है, वैसे-वैसे डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। ये एक्सपर्ट्स विभिन्न क्षेत्रों में काम कर सकते हैं –

- **लॉ एजेंसियां** - CBI, ED, क्राइम ब्रांच, पुलिस साइबर सेल
- **ज्यूडिशियल सेक्टर** - कोर्ट केसों में डिजिटल सबूत जुटाने में सहयोग
- **कॉर्पोरेट सेक्टर**- साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में
- **किंग और फिनटेक कंपनियां** - फॉड डिटेक्शन टीम का हिस्सा
- **प्राइवेट फॉरेंसिक लैब्स** - स्वतंत्र जांच एजेंसियों के साथ
- **फीलांस या कंसल्टेंट** - लॉ फर्म्स, स्टार्टअप्स, पत्रकारों के साथ सहयोग

भविष्य और स्कोप

डिजिटल फॉरेंसिक सिर्फ एक करियर नहीं, बल्कि भविष्य की सबसे जरूरी विशेषज्ञता बनती जा रही है.

डिजिटलीकरण का विस्तार
हर सेक्टर डिजिटल हो रहा है–इसका मतलब अपराध भी डिजिटल हो रहे हैं.

डेटा प्राइवेसी कानून
भारत में नया डेटा संरक्षण कानून लागू होने से अब कंपनियों को प्रोफेशनल जांच सेवाओं की जरूरत पड़ रही है.

एआई और फॉरेंसिक्स का मेल
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब डिजिटल फॉरेंसिक की जांच को और तेज बना रहा है.

एक्सपर्ट्स की भारी कमी
देशभर में ट्रेन किए गए डिजिटल फॉरेंसिक प्रोफेशनल्स की मांग बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है.

अपराध बदल रहे हैं जांच भी बदलनी होगी

जैसे-जैसे दुनिया स्क्रीन पर सिमट रही है, वैसे-वैसे अपराध भी टेक्नोलॉजी की आड़ में छिपते जा रहे हैं. लेकिन सच चाहे जितना भी गहरा छुपा हो, डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट उसे सामने लाने की ताकत रखते हैं. अगर आपको तकनीक, जांच और न्याय में रुचि है, तो यह फील्ड आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है.

क्या आपने संकल्प लिया क्या यह कि आप देश व समाज के लिए कुछ करेंगे तो देर किस बात की देश में वॉलंटियर के रूप में काम करने के तमाम अवसर मौजूद हैं। खास बात यह कि वॉलंटियरिंग कर आप न केवल मानसिक संतोष अनुभव करेंगे, बल्कि यह काम आपके व्यक्तित्व को निखारकर करियर में भी आपको फायदा पहुंचाएगा। आजकल टीनएज से ही तमाम लोग पढ़ाई के साथ देश और समाज के लिए कुछ करने की चाहत रखते हैं। अनेक जागरूक टीनएजर विभिन्न संस्थाओं से जुड़कर या स्वयं प्रयास करके समाज को बदलने के लिए वॉलंटियर या स्वयंसेवक की भूमिका निभा रहे हैं। क्या आपकी भी इच्छा होता है कि देससमाज के लिए कुछ करें, राष्ट्र निर्माण में अभी से अपना योगदान दें तो देर किस बात की आज ही कर दें शुरूआत।

आपके व्यक्तित्व को निखारकर करियर में फायदा पहुंचाएगी वॉलंटियरिंग

देश में किशोरों व युवाओं को स्वयंसेवी कार्यों में लगाने वाली तमाम सरकारी, गैर सरकारी, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं। इनमें से किसी के साथ जुड़कर आप वॉलंटियरिंग की दिशा में अपने कदम बढ़ा सकते हैं और समाज को बदलने में अपना योगदान दे सकते हैं।

गरीबों की मदद

आपके शहर, कस्बे या गांव में ऐसे लोग होंगे, जिनके पास रहने के लिए कोई मकान नहीं है। वे फुटपाथ पर या अन्यत्र खुले में ही गुजारा करते हैं। आप ऐसे लोगों को नाश्ता, खाना, सर्दी के दिनों में गर्म कपड़े या कंबल बांटने वाली संस्थाओं के लिए काम कर सकते हैं। अगर आपके शहर में ऐसी कोई संस्था नहीं मिलती, तो आप खुद ही अपने कुछ दोस्तों और अभिभावकों के साथ मिलकर यह काम कर सकते हैं।

ट्रैफिक में सहयोग

आप अपने शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू तरीके से चलाने में या किसी बड़ी खेल प्रतियोगिता, मेले आदि के आयोजन के दौरान स्वयंसेवक के रूप में काम कर प्रशासन की मदद कर सकते हैं। इसके लिए आयोजकों या ट्रैफिक पुलिस विभाग से संपर्क करें। आप लोगों के बीच जाकर ट्रैफिक नियमों के पालन के बारे में जागरूकता अभियान भी चला सकते हैं। किसी प्राकृतिक आपदा के समय भी आप वॉलंटियर के रूप में सहयोग कर सकते हैं।

पर्यावरण की खातिर

पर्यावरण को लेकर आज किसी छोटे शहर से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक चिंता व्याप्त है। आप अपने शहर, कस्बे के पर्यावरण को दुरुस्त रखने के लिए पौधे लगाने से लेकर प्रदूषण कम करने के तमाम प्रयासों में सहयोग कर सकते हैं।

अस्पतालों में सेवा

कई अस्पतालों, संस्थाओं को नेत्र शिविर या रक्तदान शिविर जैसे कई अभियानों के लिए स्वयंसेवक चाहिए होते हैं। इसी तरह कई अनाथालय, सीनियर सिटिजन सेंटर आदि को भी वॉलंटियर्स की जरूरत होती है। आप ऐसे मौकों पर अपनी सेवाएं दे सकते हैं।

ऑनलाइन वॉलंटियरिंग

कई सामाजिक संस्थाएं अपनी वेबसाइट, ब्लॉग, जर्नल आदि को चलाने और ऑनलाइन मार्केटिंग व कम्युनिकेशन के लिए वॉलंटियर्स की मदद लेती हैं। यदि आपके पास कम्प्यूटर और इंटरनेट है तथा आप थोड़ी टेक्निकल, डिजिटल जागरूकता रखते हैं, तो किसी संस्था को इन कार्यों में मदद कर सकते हैं। खास बात यह है कि इस तरह की समाज सेवा आप घर बैठे ही कर सकते हैं!

एनसीसी, स्काउट-गाइड

नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी) देश सेवा व समाज सेवा के लिए एक बेहतरीन संगठन है। इसमें एक तरह की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। इस तरह एनसीसी युवाओं को सैन्य सेवाओं में शामिल होने के लिए भी प्रेरक वातावरण तैयार करता है। यही नहीं, कई सैन्य सेवाओं में एनसीसी प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को तरजीह भी दी जाती है। एनसीसी के कैडेटों को कई तरह के सामाजिक कार्यों में लगाया जाता है।

उप मुख्यमंत्री से कराया गया लोकार्पण, अब उपेक्षा और अव्यवस्था की भेंट चढ़ रही चौपाटी

पारियोजना आज प्रशासनिक उदासीनता और योजनागत विफलता का प्रतीक बनती जा रही है

नई दृष्टिबिंदु / कवर्धा

पंडरिया नगर के मध्य स्थित क्षेत्र को आधुनिक स्वरूप प्रदान करने तथा नागरिकों को व्यापारिक एवं मनोरंजन संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लाखों रुपये की लागत से निर्मित सवर्सुविधायुक्त चौपाटी आज अपनी दुदर्शा पर स्वयं प्रश्नचिन्ह खड़ा करती दिखाई दे रही है। जिस महत्वाकांक्षी परियोजना का लोकार्पण प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव के करकमलों द्वारा बड़े ही भव्य आयोजन के साथ किया गया था, वही परियोजना आज प्रशासनिक उदासीनता और योजनागत विफलता का प्रतीक बनती जा रही है।

लोकार्पण के अवसर पर चौपाटी को पंडरिया नगर की नई पहचान, स्थानीय रोजगार संवर्धन का केंद्र तथा नगरीय विकास की आधारशिला बताया गया था। किंतु समय बीतने के साथ ही इन दावों की वास्तविकता सामने आने लगी। वतर्मान में चौपाटी परिसर में निर्मित अधिकांश दुकानें बंद पड़ी हैं और उन पर ताले लटक रहे हैं। नगर पालिका परिषद द्वारा दुकानों के आवंटन हेतु दो बार नीलामी प्रक्रिया आयोजित की गई, किंतु दोनों प्रयास अपेक्षित सफलता प्राप्त करने में असफल रहे।

यह स्थिति निर्माण कार्य की व्यवहारिकता और पूर्व नियोजन पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। यदि व्यापारिक गतिविधियों की संभावनाओं एवं बाजार की मांग का समुचित मूल्यांकन नहीं किया गया था, तो आखिरकार इतनी बड़ी राशि खर्च कर इस परियोजना को मूर्त रूप देने की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? नगरवासियों का मानना है कि बिना दूरदर्शी रणनीति और व्यावहारिक अध्ययन के तैयार की गई योजनाएं अक्सर इसी प्रकार निष्प्रभावी सिद्ध होती हैं।

चौपाटी की बदहाली केवल बंद दुकानों तक सीमित नहीं है। परिसर को आकर्षक स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से लगाए गए पौधे भी संरक्षण एवं नियमित देखरेख के अभाव में सूखने लगे हैं। अनेक पौधे पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं, जबकि शेष पौधे भी जीवन संघर्ष करते दिखाई दे रहे हैं। जिस परिसर को हरियाली और सौंदर्यीकरण का केंद्र बनाया जाना था, वहां आज उपेक्षा और लापरवाही के स्पष्ट चिन्ह परिलक्षित हो रहे हैं।

स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि विकास कार्यों में करोड़ों और लाखों रुपये व्यय करने के बाद उनके रखरखाव एवं संचालन की जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं लिया जाता। निर्माण कार्य पूर्ण होने और लोकार्पण समारोह संपन्न होते ही अधिकांश परियोजनाएं प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार हो जाती हैं। परिणामस्वरूप जनधन से निर्मित परिसंपत्तियां अल्प समय में ही अपनी उपयोगिता और प्रासंगिकता खो बैठती हैं।

नगर के प्रबुद्ध नागरिकों का कहना है कि किसी भी विकास परियोजना का उद्देश्य केवल निर्माण कार्य पूर्ण कराना नहीं, बल्कि उसका सतत संचालन और जनहित में प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना भी होना चाहिए। यदि लाखों रुपये की लागत से निर्मित दुकानें खाली पड़ी हों, पौधे सूख रहे हों और पूरा परिसर वीरानी का दंश झेल रहा हो, तो यह न केवल प्रशासनिक अक्षमता का परिचायक है बल्कि सार्वजनिक धन के समुचित उपयोग पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है।

वतर्मान परिस्थितियों को देखते हुए आशंका व्यक्त की जा रही है कि यदि समय रहते सुधारात्मक एवं पुनर्जीवन संबंधी कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले वर्षों में यह चौपाटी पूर्णतः जर्जर अवस्था में पहुंच सकती है। जिस परियोजना को नगर के विकास और गौरव का प्रतीक बताया गया था, वही आज अव्यवस्था, कुप्रबंधन और जवाबदेही के अभाव का जीवंत उदाहरण बनती जा रही है।

अब नगरवासियों की निगाहें प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर टिकी हुई हैं। जनता यह जानना चाहती है कि क्या इस निष्प्रभावी होती परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए कोई ठोस कायर्योजना तैयार की जाएगी? क्या खाली पड़ी दुकानों के उपयोग एवं संचालन के लिए नई रणनीति बनाई जाएगी? क्या परिसर के संरक्षण एवं रखरखाव के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी? अथवा यह चौपाटी भी उन सरकारी परियोजनाओं की सूची में शामिल हो जाएगी, जिनकी उपयोगिता केवल लोकार्पण समारोहों और प्रचार-प्रसार तक ही सीमित रह जाती है?

पंडरिया नगर में आज यही चर्चा का विषय बना हुआ है कि विकास का प्रतीक बताई गई चौपाटी आखिर इतनी शीघ्र बदहाली का शिकार कैसे हो गई और इसके लिए उत्तरदायी कौन है।

खास खबर

पुलिस अधीक्षक ने सेवानिवृत्त सहायक उप निरीक्षक वासुदेव को सेवानिवृत्त पर दी विदाई

नई दृष्टिबिंदु / कवर्धा

पुलिस अधीक्षक कबीरधाम धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित पटेल के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कार्यालय कबीरधाम में सहायक उप निरीक्षक वासुदेव साय पैकरा के सेवानिवृत्त होने के अवसर पर गरिमामय विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभागीय अधिकारियों एवं कमर्चारियों ने उनके दीर्घ, समर्पित एवं उत्कृष्ट सेवाकाल को स्मरण करते हुए उन्हें ससम्मान विदाई दी।

वासुदेव साय पैकरा ने 31 अक्टूबर 1989 को मध्यप्रदेश के इंदौर में आरक्षक पद पर पुलिस विभाग में अपनी सेवाओं का शुभारंभ किया था। अपने लगभग 36 वर्ष 7 माह के सेवाकाल के दौरान उन्होंने जिला राजनांदगांव एवं जिला कबीरधाम के विभिन्न थाना एवं इकाइयों में कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन एवं ईमानदारी के साथ सेवाएं प्रदान कीं। सेवाकाल के दौरान उन्होंने थाना सिटी कोतवाली, थाना पांडातराई, थाना कुकदुर, थाना कुंडा, थाना पंडरिया, थाना चिल्फी एवं थाना बोडला में विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया।

अपने उत्कृष्ट कार्य निष्पादन एवं विभाग के प्रति समर्पण के फलस्वरूप श्री पैकरा ने आरक्षक से प्रधान आरक्षक तथा प्रधान आरक्षक से सहायक उप निरीक्षक पद तक पदोन्नति प्राप्त की। सेवानिवृत्ति के समय वे थाना बोडला में पदस्थ थे तथा अपने सौम्य व्यवहार, कायर्कुशलता एवं कर्तव्यपरायणता के लिए विभाग में विशेष पहचान रखते थे। विदाई समारोह के दौरान पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह द्वारा श्री पैकरा को श्रीफल, शॉल एवं स्मृति-चिन्ह भेंट कर उनके उत्कृष्ट सेवाकाल की सराहना की गई तथा पुलिस परिवार की ओर से उनके स्वस्थ, सुखद एवं सम्मानपूर्ण भविष्य की कामना की गई। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि श्री पैकरा की निष्ठा, अनुशासन एवं सेवाभाव युवा पुलिस कमिर्यों के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा।

समारोह में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित पटेल, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय आशीष शुक्ला, उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती अंजू कुमारी सहित पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने पुष्पगुच्छ भेंट कर श्री पैकरा के उज्ज्वल एवं सुखमय जीवन की शुभकामनाएं देते हुए उनकी सेवाओं को सम्मानपूर्वक नमन किया। कबीरधाम पुलिस परिवार ने वासुदेव साय पैकरा के समर्पण, कर्तव्यनिष्ठा एवं अनुकरणीय सेवाओं के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए उन्हें भावभीनी एवं गौरवपूर्ण विदाई दी।

आयुक्त ने की पानी को उबालकर पीने की अपील, पीलिया से ग्रसित 3 मरीजों का किया जा रहा उपचार

राजनांदगांव। जिले में पीलिया बीमारी से ग्रसित 5 मरीज है, जिनका उपचार जिला चिकित्सालय राजनांदगांव में किया जा रहा है। जिसमें से एक मरीज स्वस्थ होकर हास्पिटल से डिस्चार्ज हो गए है। एक का घर पर इलाज चल रहा है तथा 3 मरीज का इलाज अभी जिला चिकित्सालय में जारी है। जिले में पीलिया के कुछ मरीज पाए गए है। बीमारी के स्थानीय कारणों के संबंध में जांच की जा रही है। नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने नागरिकों से अपील की है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए पानी को उबालकर पीएं तथा क्लोरीन टेबलेट युक्त पेयजल का ही उपयोग करें।

नशा पर कबीरधाम पुलिसने किया बड़ा प्रहार संदिग्ध इलाकों में दबिश, गांजा-शराब जप्त

जिलेभर में नशे के विरुद्ध विशेष कार्रवाई जारी

नई दृष्टिबिंदु / कवर्धा

जिले में नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने कबीरधाम पुलिस लगातार अभियान चला रही है। पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल एवं अमित पटेल के मार्गदर्शन में जिलेभर में नशे के विरुद्ध विशेष कार्रवाई जारी है।

इसी क्रम में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को प्राप्त सूचना के आधार पर कवर्धा एवं साइबर थाना के साथ संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कार्रवाई की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल स्वयं कवर्धा शहर के देवारपारा क्षेत्र पहुंचे और पुलिस टीम के साथ छापेमार कार्रवाई का नेतृत्व किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने संदिग्ध मकानों एवं स्थानों की तलाशी ली। तलाशी के दौरान कई स्थानों से अवैध रूप से संग्रहित शराब बरामद की गई। वहीं कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने घरों के पीछे के हिस्से में जमीन के भीतर गांजा छिपाकर रखा गया था।

पुलिस ने मौके पर गांजे को बरामद कर जप्ती की की। जप्त किए गए मादक पदार्थ एवं अवैध शराब के संबंध में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक सिंह ने मौके पर उपस्थित लोगों एवं स्थानीय नागरिकों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नशे का कारोबार समाज और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बर्बाद करता है तथा ऐसे अवैध कार्यों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

उन्होंने कहा कि अवैध शराब, गांजा एवं अन्य मादक पदार्थों का कारोबार पूरी तरह छोड़ दें। यह रास्ता न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि समाज और परिवार को भी नुकसान पहुंचाता है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उन्हें संस्कार और बेहतर वातावरण प्रदान करें ताकि वे पढ़-लिखकर समाज एवं देश के विकास में योगदान दे सकें। बच्चों का भविष्य नशे के कारोबार में नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार और अच्छे संस्कारों में है।

उन्होंने कहा कि कबीरधाम पुलिस नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है और जिले में कहीं भी अवैध मादक पदार्थों की बिक्री, परिवहन अथवा भंडारण की सूचना मिलने पर तत्काल कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आम नागरिकों से भी अपील करती है कि वे नशे से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना पुलिस को दें, उनकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में नशा पर प्रहार अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा और युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए पुलिस द्वारा जनजागरूकता कार्यक्रमों के साथ-साथ प्रभावी कानूनी कार्रवाई भी की जाती रहेगी।

इस कार्रवाई में डीएसपी आशीष शुक्ला, कोतवाली थाना प्रभारी योगेश कश्यप, अठळऋ प्रभारी महेश प्रधान, साइबर थाना प्रभारी उमाशंकर राठौर, श्रीमती दिव्या शर्मा, श्रीमती शालिनी वर्मा सहित पीएसआई एवं थाना कोतवाली की टीम के अधिकारी एवं कमर्चारी शामिल रहे। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों में हड़कंप की स्थिति देखी गई है। कबीरधाम पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में कानून व्यवस्था एवं समाज की सुरक्षा के लिए ऐसे अभियान भविष्य में भी और अधिक प्रभावी रूप से जारी रहेंगे।

अवैध खनिज उत्खनन व परिवहन पर 4 वाहन जब्त

बालोद। जिले में खनिज संसाधनों के संरक्षण तथा अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा लगातार सघन कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार खनिज विभाग की टीम ने 03 जून 2026 को गुण्डरदेही विकासखंड अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण कर अवैध खनिज गतिविधियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की। जिला खनि अधिकारी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान अर्जुन्दा तहसील के ग्राम खेरूद तथा गुण्डरदेही तहसील के ग्राम कोटगांव में गौण खनिज मिट्टी एवं रेत के अवैध उत्खनन तथा परिवहन की गतिविधियां पाई गईं। मौके पर कार्रवाई करते हुए खनिज विभाग की टीम ने अवैध कार्य में संलिप्त दो जेसीबी मशीन, एक हाईवा तथा एक ट्रैक्टर-ट्रॉली सहित कुल चार वाहनों को जब्त किया।

जागरूकता सेमिनार में ई-फाईलिंग, टीडीएस व टीसीएस कटौती के संबंध में दी गई विस्तार से जानकारी

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

कलेक्टर जितेन्द्र यादव की उपस्थिति में जिला कार्यालय सभाकक्ष में आयकर विभाग द्वारा टीडीएस व टीसीएस एवं आयकर अधिनियम-2025 के संबंध में जागरूकता एवं प्रशिक्षण सेमिनार का आयोजन किया गया।

कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि आयकर संबंधी प्रावधानों की सही जानकारी होना आवश्यक है, जिससे वित्तीय कार्यों में पारदशिर्ता बनी रहे तथा विभागीय दायित्वों का समय पर निर्वहन किया जा सके। उन्होंने सभी अधिकारियों को प्रशिक्षण का लाभ लेकर अपने विभागों में भी जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। सेमिनार में विभिन्न विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) ने भाग लिया।

आयकर अधिकारी (टीडीएस) भिलाई रजनी श्रीकुमार ने आयकर अधिनियम-2025 में किए गए महत्वपूर्ण प्रावधानों एवं परिवतर्नों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नए आयकर अधिनियम में विभिन्न धाराओं एवं प्रपत्रों का सरलीकरण किया गया है। टीडीएस की कटौती, समय पर जमा करने तथा त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया। उन्होंने कहा कि टीडीएस कटौती एवं जमा की समय-सीमा का पालन करना सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। प्रशिक्षण के दौरान टीडीएस की विभिन्न दरों, वेतनभोगी कमर्चारियों तथा अन्य भुगतानों पर लागू प्रावधानों की जानकारी दी गई। साथ ही विलंब से विवरणी प्रस्तुत करने पर लगने वाले शुल्क, दंडात्मक प्रावधानों एवं सुधार विवरणी से संबंधित नियमों की विस्तार से जानकारी प्रदान की गई।

सेमिनार में अधिकारियों द्वारा टीडीएस कटौती, एसएनए खातों, चालान जमा करने की प्रक्रिया, पेशेवर सेवाओं पर टीडीएस की दर, नकद निकासी पर लागू प्रावधान तथा विभिन्न व्यावहारिक समस्याओं से संबंधित प्रश्न पूछे गए, जिनका आयकर विभाग की टीम ने विस्तार से समाधान किया। आयकर विभाग की टीम ने आयकर अधिनियम-2025, टीडीएस प्रावधानों तथा ई-फाइलिंग से संबंधित उपयोगी डिजिटल संसाधनों एवं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जानकारी साझा की। सेमिनार में सीईओ जिला पंचायत सुरूचि सिंह, अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर प्रेमप्रकाश शर्मा, जिला कोषालय अधिकारी दिलीप सिंह सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

खेत बचाओ अभियान के तहत किसानों को मृदा व जल संरक्षण की दी गई जानकारी

15 जून तक संचालित किया जाएगा अभियान, पोषक तत्व प्रबंधन व टिकाऊ कृषि पद्धतियों के संबंध में किया जाएगा जागरूक

नई दृष्टिबिंदु / मोहला

जिला प्रशासन के निर्देशन एवं उपसंचालक कृषि के मार्गदर्शन में विकासखंड मोहला के ग्राम पंचायत आलकन्हार में खेत बचाओ अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसानों को रासायनिक उर्वरकों के संतुलित एवं वैज्ञानिक उपयोग के संबंध में जानकारी प्रदान की गई तथा मृदा उर्वरता बनाए रखने हेतु नील हरित शैवाल एवं हरी खाद वाली फसलों जैसे सनई, ढैंचा एवं मूंग के उत्पादन एवं उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान किसानों को जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, जैविक खादों के अधिकतम उपयोग तथा कृषि भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के उपायों की विस्तृत जानकारी दी गई। कृषकों को बताया गया कि रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग के साथ जैविक एवं प्राकृतिक स्रोतों का समावेश करने से मृदा की उवर्राशक्ति बनी रहती है तथा उत्पादन लागत में कमी आती है। कृषि विभाग द्वारा विकासखंड मोहला के ग्राम मांडिंग-पिंडिंग भुर्सा, रेंगाकठेरा एवं आलकन्हार में खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की गई है। ग्राम पंचायत मांडिंग-पिंडिंग एवं भुर्सा में आयोजित अभियान के दौरान उपस्थित किसानों को रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम कर वैकल्पिक उपायों जैसे हरी खाद, ढैंचा, गोबर खाद, फसल अवशेष प्रबंधन, एकीकृत कीट प्रबंधन तथा एकीकृत उर्वरक प्रबंधन को अपनाने की सलाह दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, सरपंच, पंच, कृषक एवं ग्रामवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

जिला प्रशासन के निर्देशानुसार चयनित ग्रामों में यह अभियान 15 जून 2026 तक संचालित किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत किसानों को मृदा एवं जल संरक्षण, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन तथा टिकाऊ कृषि पद्धतियों के संबंध में जागरूक किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार द्वारा किसानों को समन्वित कृषि प्रणाली अपनाने, कृषि भूमि के संरक्षण एवं संवर्धन तथा उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। खेत बचाओ अभियान के माध्यम से किसानों को पर्यावरण-अनुकूल एवं टिकाऊ खेती की तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

कलेक्टर ने की खाद भंडारण व बीज वितरण की समीक्षा, लंबित प्रकरणों के निराकरण के दिए निर्देश

नई दृष्टिबिंदु / मोहला

कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की साप्ताहिक बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं लंबित कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अग्रिम खाद एवं बीज वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से खाद भंडारण की स्थिति की जानकारी ली तथा बीज वितरण कार्य में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती भारती चंद्राकर, अपर कलेक्टर जीआर मरकाम, अपर कलेक्टर मिथलेश डोंडे, एसडीएम मोहला हेमेंद्र भुआर्य, एसडीएम मानपुर अमित नाथ योगी, डिप्टी कलेक्टर डीआर ध्रुव सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने आजीविका संवर्धन से जुड़े विषयों की समीक्षा करते हुए पात्र हितग्राहियों एवं समूहों को पट्टे पर तालाब उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे मत्स्य पालन एवं अन्य आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तथा ग्रामीणों की आय में वृद्धि होगी। बैठक में सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि जनसामान्य से प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान शासन की सवोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने लंबित राजस्व प्रकरणों की भी समीक्षा की तथा राजस्व अधिकारियों को प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व मामलों में अनावश्यक विलंब से आम नागरिकों को परेशानी होती है, इसलिए निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण किया जाए।

बैठक में उन्होंने शेष धान उठाव की स्थिति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को शत-प्रतिशत उठाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही सहकारी समितियों की नियमित बैठक आयोजित कर आवश्यक निर्णय लेने और कार्यों की सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने आयुष्मान कार्ड निर्माण एवं सिकल सेल स्क्रीनिंग अभियान की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को इन महत्वपूर्ण योजनाओं में अपेक्षित प्रगति लाने तथा अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए भूमि चिन्हांकन में हो रहे विलंब पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की और संबंधित अधिकारियों को शीघ्र आवश्यक कार्रवाई पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में मोबाइल टॉवर स्थापना संबंधी प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि दूरसंचार सुविधाओं का विस्तार शासन की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने चिन्हांकित स्थानों पर मोबाइल टॉवर स्थापना हेतु आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए। मौके पर उन्होंने समाज कल्याण, महिला बाल विकास, मत्स्य पालन, पशुपालन विभाग, आदिवासी विभाग, शिक्षा विभाग जैसे अन्य विभागों के योजनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए विभागों को निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समन्वय के साथ कार्य करने तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने तथा लाभान्वित करने के निर्देश दिए।

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर, तहसील व जिला-दुर्ग

-:: ईश्तहार ::-

(रा.प्र.क्रं. /अ/6 वर्ष 2025-26)

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक -श्री धीरज कुमार आ./ध.प. श्री रामाश्रय निवासी - हाऊसिंग बोर्ड भिलाई द्वारा ग्राम - कुरुद प.ह.नं. 46 रा.नि.मं. कोहका तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 1383/1 रकबा 0.0220 हे. भूमि को रजिस्ट्री बैनामा के आधार पर दिनांक 09/10/2020 के आधार पर पर विक्रेता आलोक कुमार लुनिया/ स्व. जे.के. लुनिया से क्रय किया गया है, कि रजिस्ट्री बैनामा के आधार पर नामांतरण किये जाने बाबत् आवेदन पत्र मय बैनांमा की छाया प्रति प्रस्तुत किया गया है।

अतः उपरोक्त भूमि के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 16/06/2026 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 25/05/2026 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से जारी किया गया है।

अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर, तहसील व जिला-दुर्ग

-:: ईश्तहार ::-

(रा.प्र.क्रं. /अ/6 वर्ष 2025-26)

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक -श्री.टी. अप्पिली आ./ध.प. श्री तोगी रमेश निवासी - हाऊसिंग बोर्ड भिलाई द्वारा ग्राम - कुरुद प.ह.नं. 46 रा.नि.मं. कोहका तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 1383/1 रकबा 0.0140 हे. भूमि को रजिस्ट्री बैनामा के आधार पर दिनांक 26/11/2019 के आधार पर पर विक्रेता आलोक कुमार लुनिया/ स्व. जे.के. लुनिया से क्रय किया गया है, कि रजिस्ट्री बैनामा के आधार पर नामांतरण किये जाने बाबत् आवेदन पत्र मय बैनांमा की छाया प्रति प्रस्तुत किया गया है।

अतः उपरोक्त भूमि के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 16/06/2026 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 27/05/2026 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से जारी किया गया है।

अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर, तहसील व जिला-दुर्ग

-:: ईश्तहार ::-

(रा.प्र.क्रं. /अ/6 वर्ष 2025-26)

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक -भूखन कुमार आ./ध.प. स्व. मिलन सिन्हा निवासी - आर्य नगर कोहका भिलाई द्वारा ग्राम - कोहका प.ह.नं. 45. रा.नि.मं. कोहका तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 512 रकबा 760 वर्गफीट भूमि को रजिस्ट्री बैनामा के आधार पर दिनांक 09/12/25 के आधार पर पर पक्षकार भीखम कुमार सिन्हा / स्व. मिलन सिन्हा से क्रय किया गया है, कि रजिस्ट्री बैनामा के आधार पर नामांतरण किये जाने बाबत् आवेदन पत्र मय बैनांमा की छाया प्रति प्रस्तुत किया गया है।

अतः उपरोक्त भूमि के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 18/06/2026 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 27/05/2026 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से जारी किया गया है।

अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर

'पर्यावरण धर्म' निभा रहे भिलाई के बालू राम वर्मा, तनख्वाह का 10% लगाकर उगाए 20 हजार पेड़

1983 से जुटे हैं हरियाली के मिशन में, 2006 में ही शुरू किया था घर-घर कचरा संग्रह

आलोक तिवारी/ भिलाई

पर्यावरण दिवस पर भिलाई के बालू राम वर्मा ने प्रकृति प्रेम की ऐसी मिसाल पेश की है जो सबके लिए प्रेरणा है। 1983 से वह लगातार पर्यावरण संरक्षण को अपना धर्म मानकर काम कर रहे हैं। हर महीने अपनी तनख्वाह का 10% हिस्सा पेड़-पौधों पर खर्च करते हैं। अब तक उनके लगाए 15 से 20 हजार पौधे पेड़ बनकर शहर को छाया दे रहे हैं।

गुठली से तैयार किए हजारों पौधे

1983 में बीएसपी की नौकरी करने भिलाई आए बालू राम ने यहां का प्रदूषण देखकर पेड़ लगाने का संकल्प लिया। वे बताते हैं, "लोग धार्मिक कार्यों में 10% पैसा लगाते हैं, मैंने सोचा क्यों न अपनी तनख्वाह का 10% पर्यावरण के धर्म में लगाऊं।" शुरुआत में नर्सरी कम थीं तो वे लोगों से फलों की गुठली मांगकर पौधे तैयार करते थे। ट्री गार्ड लगाकर सींचते और बड़ा पेड़ बनाते। रिटायर होने के बाद भी उन्होंने रिटायरमेंट के पैसे का 10% पेड़ों की सेवा में लगाया।

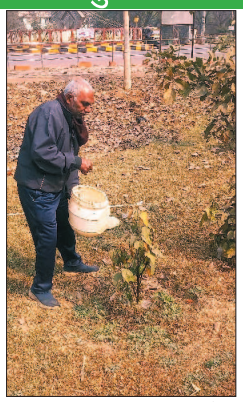

सेक्टर-1 से 11, खुर्सीपार, सुपेला लाल मैदान से लेकर मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों तक उनके लगाए पेड़ आज हरियाली फैला रहे हैं। हर साल वह अपनी नर्सरी से 10 से 15 हजार पौधे निशुल्क बांटते भी हैं।

2006 में ही शुरू किया स्वच्छता अभियान

बालू राम ने 2006 में ही स्वच्छता का काम शुरू कर दिया था। बीएसपी में नौकरी के साथ-साथ उन्होंने घर-घर कचरा उठाने का बीड़ा उठाया। इसके लिए सीपीएफ से डेढ़ लाख का लोन लेकर 3 रिक्शा खरीदे। बीएसपी से बात कर डंपिंग एरिया भी तय कराया। वे कहते हैं, "मोदी जी अब स्वच्छता की बात करते हैं, हमने ये काम 18 साल पहले शुरू कर दिया था।" परिवार के विरोध के बावजूद वे डटे रहे।

सास की स्मृति में बनाई संस्था

2006 में ही उन्होंने अपनी सास की स्मृति में 'मोम बाइ वर्मा कल्याण समिति' बनाई और सेवा का काम आगे बढ़ाया। उनका मानना है कि प्रकृति हमें हवा, पानी सब फ्री देती है, तो धरती का कर्ज चुकाना हमारा नैतिक दायित्व है। एकला चलो की राह पर चलते हुए बालू राम ने पर्यावरण और स्वच्छता के क्षेत्र में लोगों में अलख जगाई है।

'एक शिशु-एक पौधा' अभियान बना पर्यावरण संरक्षण की मिसाल, 55 हजार से अधिक पौधे

डॉ. मानसी गुलाटी के मार्गदर्शन में 25 साल से चल रहा अभियान, नवजात के साथ मिलता है हरियाली का तोहफा

दुर्ग। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में श्री रमेश चंद्र फाउंडेशन का 'एक शिशु - एक पौधा' अभियान समाज के लिए प्रेरणा बन रहा है। पिछले 25 साल से चल रहे इस अभियान के तहत नवजात शिशु के जन्म पर परिवार को एक पौधा भेंट किया जाता है। अब तक 55,000 से अधिक पौधों का वितरण किया जा चुका है।

बच्चे की तरह पौधे की देखभाल का संकल्प

फाउंडेशन की निदेशक एवं वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. मानसी गुलाटी के मार्गदर्शन में यह अभियान चल रहा है। इसका उद्देश्य जन्म जैसे सुखद अवसर को प्रकृति से जोड़ना है। परिवारों को संदेश दिया जाता है कि जिस तरह वे अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं, उसी तरह पौधे की भी देखभाल करें। इससे बच्चे और प्रकृति के बीच भावनात्मक रिश्ता बनता है।

नियमित फॉलो-अप से हो रहा संरक्षण

डॉ. मानसी गुलाटी ने बताया कि पौधे बांटने के साथ ही उनके संरक्षण के लिए नियमित फॉलो-अप भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई से निपटने के लिए वृक्षारोपण और जनभागीदारी बहुत जरूरी है। वृक्ष केवल पर्यावरण संतुलन ही नहीं रखते, बल्कि ऑक्सीजन, छाया और औषधि का भी स्रोत हैं। भारतीय संस्कृति में भी वृक्षों को जीवन का आधार माना गया है।

'हर घर की यही परंपरा'

फाउंडेशन का मानना है कि यदि हर परिवार जीवन के अहम मौकों पर एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल का संकल्प ले, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और हरित वातावरण बनाया जा सकता है। 'एक शिशु के जन्म पर एक पौधा, और एक पौधे के माध्यम से हरित भविष्य की ओर एक कदम' के संकल्प के साथ यह अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है। 'एक बच्चा - एक पौधा, हर घर की यही परंपरा' का नारा देकर फाउंडेशन समाज को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रहा है।

सांसद विजय बघेल ने बाबा रुक्खडनाथ धाम में किए दर्शन, पश्चिममुखी हनुमान मंदिर में की पूजा

गोबर से निर्मित देश की पहली हनुमान प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है नारदा का यह मंदिर

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई-नारदा

दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल मंगलवार को ग्राम नारदा स्थित प्रसिद्ध बाबा रुक्खडनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने यहां पश्चिममुखी हनुमान मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर भगवान हनुमान का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की सुख, समृद्धि और जनकल्याण की कामना की।

धीरेंद्र शास्त्री भी कर चुके हैं उल्लेख

ग्राम नारदा का यह पश्चिममुखी हनुमान मंदिर अपनी अनूठी विशेषता के लिए जाना जाता है। यह हिन्दुस्तान का पहला ऐसा मंदिर माना जाता है, जहां भगवान हनुमान की प्रतिमा गाय के गोबर से निर्मित है। प्रसिद्ध कथा वाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भी अपनी कथा में इस मंदिर का उल्लेख कर चुके हैं। इसके बाद इस धाम की ख्याति और बढ़ गई है।

'सनातन परंपराओं का संदेश देते हैं ऐसे स्थल'

सांसद विजय बघेल ने मंदिर परिसर का अवलोकन किया और इसकी आध्यात्मिक व सांस्कृतिक महत्ता की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक स्थल भारतीय संस्कृति, सनातन परंपराओं और गौ संवर्धन का संदेश जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं।

ये रहे मौजूद

इस अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य रविशंकर सिंह, ग्राम सरपंच विपिन शर्मा समेत क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिक, श्रद्धालु और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने बाबा रुक्खडनाथ धाम और पश्चिममुखी हनुमान मंदिर में दर्शन कर प्रदेश और देश की उन्नति, सुख समृद्धि तथा खुशहाली की कामना की।

बंद कोल डिपो में चोरी, गार्ड से मारपीट कर वारदात को दिया अंजाम

बिलासपुर। मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत करी स्थित हिंद एनर्जी एंड कोल के बंद पड़े कोल डिपो में मंगलवार देर रात नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोलकर केबल, लोहे का सामान और पाइप चोरी कर लिया। चोरी का विरोध करने पर बदमाशों ने ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट भी की और उसे डराने-धमकाने के बाद सामान लेकर फरार हो गए। डिपो प्रबंधन की ओर से घटना की शिकायत मस्तूरी थाने में की गई है। इस पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर मामले की जांच में लिया है। मस्तूरी क्षेत्र के करी स्थित हिंद एनर्जी का कोल डिपो पिछले कुछ समय से बंद है। मंगलवार रात कुछ नकाबपोश बदमाश डिपो परिसर में घुस गए और वहां रखे कीमती केबल, लोहे के सामान तथा पाइप को चोरी करने लगे। इस दौरान ड्यूटी पर मौजूद सुरक्षा गार्ड की नजर उन पर पड़ गई। गार्ड ने बदमाशों को रोकने और उनकी पहचान करने का प्रयास किया, लेकिन बदमाशों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। अचानक हुए हमले से गार्ड घबरा गया और बदमाश मौके का फायदा उठाकर चोरी का सामान लेकर फरार हो गए।

बीएसपी प्रवर्तन विभाग ने की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त

सेक्टर-6 के 40 अनफिट आवासों समेत 72 आवास खाली कराए, 53 बिजली कनेक्शन काटे

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रवर्तन विभाग ने मई 2026 में टाउनशिप क्षेत्र में अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान कुल 21,800 वर्गफीट मूल्यवान भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। साथ ही रोड सेफ्टी और नगर व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई अहम कदम उठाए गए।

72 आवासों से हटाए कब्जे

अभियान में सेक्टर-6 स्थित अनफिट ब्लॉकों के 40 आवासों से अवैध कब्जे हटाए गए। इसके अलावा टाउनशिप के विभिन्न क्षेत्रों में 32 अन्य आवासों को भी कब्जा मुक्त कराया गया। 16 स्थानों पर कार्रवाई कर बीएसपी की 21,800 वर्गफीट भूमि को अतिक्रमण से खाली कराया गया।

सिविक सेंटर व पंथी चौक में कार्रवाई

सिविक सेंटर और पंथी चौक क्षेत्र में अवैध ठेलों और अस्थायी अतिक्रमणों को हटाया गया। अवैध खाद्य सामग्री के ठेलों को हटाकर यातायात और सार्वजनिक सुविधाओं को सुचारु किया गया।

975 बैनर-पोस्टर हटाए, 53 कनेक्शन काटे

सड़क सुरक्षा और नगर सौंदर्यीकरण के लिए 25 अवैध होर्डिंग संरचनाएं हटाई गईं। विभिन्न क्षेत्रों से 975 अवैध बैनर और पोस्टर भी हटाए गए। नियम तोड़ने वाले आवासों, दुकानों और अवैध परिसरों के 53 विद्युत कनेक्शन काटे गए।

अधिकारियों की टीम रही सक्रिय

यह अभियान महाप्रबंधक प्रभारी (नगर सेवाएं विभाग) ए. बी. श्रीनिवास के निर्देशन में चला। नेतृत्व सहायक महाप्रबंधक (प्रवर्तन विभाग) रेमी थॉमस ने किया। कार्रवाई में सहायक प्रबंधक मुकुन्द दास मानिकपुरी, संपदा निरीक्षक राममूर्ति, रमाकांत यादव, भगवान, बलराम शुक्ला, ललन सिंह, अजय मिश्रा, ज्ञानचंद जैन, राम समेत पुरुष और महिला सुरक्षा कर्मियों का योगदान रहा।

विभाग ने अवैध कब्जाधारियों को चेतावनी दी है कि वे संभावित नुकसान और प्रशासनिक कार्रवाई से बचने के लिए खुद ही अवैध कब्जे और निर्माण सामग्री हटा लें। बीएसपी के नियमों का पालन करें।

GOSWWAMI
FLEX PRINTING
ADVERTIZER
भिलाई में सबसे सस्ता, सबसे अच्छा
Hoardings • Flex Banner • Vinyl Printing
One Way Vision • Glow Sign Board
93290-13334, 74711-15735
goswamiflex@gmail.com
Address - 3rd Floor Shop No-1, Arora Tower, M.C. Market

10वीं, 12वीं, स्नातक एवं स्नातकोत्तर पास छात्र-छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए
फायर एवं सेफ्टी प्रशिक्षण
नौकरी में सहायक
प्रवेश प्रारंभ सत्र 2026-2027
निजी कंपनियां जैसे पावर प्लांट, सीमेंट प्लांट, स्टील प्लांट, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत नौकरियाँ मिलती है।
प्रशिक्षण शुल्क में विशेष छूट
सरकारी मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र दिया जाएगा
फायर एवं सेफ्टी प्रशिक्षण में प्रवेश प्रारंभ

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	क्र.	पाठ्यक्रम का नाम
1.	फायर टेक्नोलॉजी एण्ड इंडस्ट्रियल सेफ्टी	5.	पी. जी. कोर्स व्यावसायिक सेफ्टी, स्वास्थ्य व पर्यावरण मैनेजमेंट सिस्टम
2.	इंडस्ट्रियल सेफ्टी / पी. जी. इंडस्ट्रियल सेफ्टी	6.	हैल्थ सेनेटरी इंस्पेक्टर
3.	बी.एस.सी. इन फायर सेफ्टी	7.	सब- फायर ऑफिसर
4.	पी. जी. कोर्स फायर एवं इंडस्ट्रियल सेफ्टी	8.	सर्टिफिकेट इन फायरमैन-इंडस्ट्रियल सेफ्टी

(An Authorized Training Centre of AEERO)
फायर सेफ्टी एवं डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट
(मान्यता प्राप्त निजी प्रशिक्षण संस्थान)
कैंपस :- इंदिरा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, सुपेला, भिलाई, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़
ADMISSION HELPLINE: 7697212782

Baked by Suhani
Premium Homemade Cakes & Desserts
Birthday Cakes
Anniversary Cakes
Custom Theme Cakes
Serving Bhilai & Durg
baked.by.suhani
Suhani Singh
Premium Homemade Cakes & Desserts
Serving Bhilai & Durg
DM for Order
Followed by _s_andeep
Follow
Message
Order Now:
@baked.by.suhani
MO.6263734520

अर्चना
फ्लाई ऐश ब्रिक्स
निर्माता एवं विक्रेता
हैवी इंडस्ट्रीयल एरिया, भिलाई
8 इंच एवं 9 इंच में उपलब्ध है।
संपर्क करें
9329960605, 9827160605, 9098639991

"यह समाचार पत्र आलोक तिवारी द्वारा 80/बी, मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग, (छत्तीसगढ़)-490023 से आलोक तिवारी की ओर से प्रकाशित की जाती है, जिसका संपादन आलोक तिवारी द्वारा किया जाता है तथा इसका मुद्रण समय दर्शन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स द्वारा प्लॉट नं. 339/6, गली नं. 02, पाटन, थाना उतई, दुर्ग, (छ.ग.)-491111 पर किया जाता है। (समाचार चयन के लिए PRP Act, 2023 के तहत संपादक जिम्मेदार है)। समस्त विवादों का निपटारा न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।" संपादक आलोक तिवारी, मो. 74154-69100